सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 76, नई दिल्ली, सोमवार 26 मई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना जरूरी है।

03 देश में कोरोना की फिर से वापसी , डरने की जरूरत नहीं सतर्कता बरतें
06 बहुभाषी शिक्षा को मिले बढ़ावा
08 26 मई की क्रांतिः नया भारत, नया विश्वास - मोदी युग का शंखनाद

ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, इन 15 जगहों पर बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 15 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। पहले चरण के लिए स्थान चिहि्नत किए गए हैं और जल्द ही एक निजी कंपनी को निर्माण रखरखाव और संचालन का कार्य सौंपा जाएगा। प्राधिकरण उन शहरों का अध्ययन कर रहा है जहाँ ईवी चार्जिंग स्टेशन सफलतापूर्वक चल रहे हैं। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की भी जरूरत महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है।

पहले चरण में 15 स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए स्थान चिहि्नत कर लिए गए हैं। कंपनी की तलाश के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया जाएगा। स्टेशन बनाने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम उन शहरों का अध्ययन भी करेगी, जहां यह व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। इसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं। सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ानी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी योजना बनाई है।

पहले चरण में 15 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पर तीन चार्जिंग प्वाइंट होंगे। प्राधिकरण के

मुताबिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी जाएगी।

कंपनी के चयन के लिए आरएफपी तैयार हो गई है, जो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने निर्देश दिए हैं कि उन शहरों का अध्ययन किया जाए, जहां ईवी चार्जिंग स्टेशन सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। प्राधिकरण इच्छुक कंपनी को सिर्फ जमीन देगा, निर्माण समेत बाकी खर्च कंपनी ही उठाएगी।

इन स्थानों पर बनेंगे स्टेशन

सेक्टर अल्फा-टू, जगत फार्म, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पास, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, इंडिया एक्सपो मार्ट के पास, सिटी पार्क, डेल्टा-वन, डब्ल्यूएचओ सोसायटी के पास, अल्फा-वन कमर्शियल बेल्ट, सेक्टर गामा-वन रेरा कार्यालय, नॉलेज पार्क-टू स्थित एनआईईटी कॉलेज के पास, अंसल प्लाजा मॉल, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स आदि।

धौला कुआं-गुरुग्राम सड़क बनी तालाब, अंडरपास में डूबी गाड़ियां; कई पेड़ उखड़े

दिल्ली में बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। धौला कुआं-गुरुग्राम रोड पर पानी भर गया और दिल्ली-कैंट अंडरपास में वाहन डूब गए। महरौली में पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा। मई में बारिश ने ऑलटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 186 .4 मिमी दर्ज की गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

दिल्ली। देर रात आंधी और बारिश के चलते दक्षिणी दिल्ली में रविवार को भी जनजीवन प्रभावित रहा। धौला कुआं से गुरुग्राम जाने वाले मार्ग पर बारिश के पानी भर गया। वाहन चालक इसी पानी से होकर गुजर रहे थे। हालांकि कई जगह पंप लगाकर सड़क पर भरे पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली-कैंट अंडरपास में तीन से चार फीट पानी जमा हो गया था। सुबह इसमें से फंसकर एक प्राइवेट बस और एक कार बंद हो गए।

महरौली में टीबी हास्पिटल से पीटीएस चौक जाने वाले मार्ग पर एक बड़ा नीम का पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा। हालांकि अवकाश का दिन होने के चलते ट्रैफिक का दबाव नाममात्र का था, जिसके चलते जाम नहीं लगा। पेड़ गिरने से सड़क करीब एक तिहाई अवरुद्ध है।

मई में बना बारिश का ऑलटाइम रिकॉर्ड

राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का पर्याय माने जाने वाले मई महीने में इस बार ऑलटाइम रिकॉर्ड बन गया है। अभी तक 186.4 मिमी बारिश हो चुकी है। इससे पहले मई 2008 में 165 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी।

उल्लेखनीय है कि शनिवार आधी रात के बाद तेज आंधी एवं बारिश ने फिर मौसम का मिजाज बदल दिया। इस दौरान 82 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से आधी चली और 81.4 मिमी बरसात बारिश हुई।

बारिश से तापमान में आई गिरावट

बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी से राहत मिली है। आज रविवार का न्यूनतम तापमान रहा सामान्य से 6.9 डिग्री नीचे 19.8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। दिन में भी गर्मी के तेवर नरम ही रहने का पूर्वानुमान है।

बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस वे बनकर तैयार , अब जयपुर जाना होगा आसान

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वरः बहुप्रतीक्षित भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर नया अपडेट आया है। राज्य सरकार भुवनेश्वर में पुल के ऊपर की बजाय जमीन के नीचे मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इसकी तैयारियों से संबंधित अधिकांश चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं। भुवनेश्वर मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो ट्रेन की तरह भूमिगत होगी।पूर्व मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना के बारे में मीडिया को जानकारी दी। राजधानी में मेट्रो भूमिगत होगी। मेट्रो भूमिगत चलेगी।

मीडिया को जानकारी देते हुए श्री हरिचंदन ने कहा कि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। भुवनेश्वर में जिस तरह से भीड़ दिन-प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। इसीलिए भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना को भूमिगत बनाने का निर्णय लिया गया है।तत्कालीन सरकार ने भुवनेश्वर में प्रस्तावित मेट्रो रेल की आधारशिला रखी थी।पिछले साल एक जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने त्रिशूलिया के पास रतगढ़ के लेंका साही में आयोजित एक समारोह में मेट्रो रेल की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना पर कुल 6255 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। परियोजना के पहले चरण में यह मेट्रो रेल भुवनेश्वर हवाई अड्डे से त्रिशूलिया चैक तक 26 किलोमीटर तक चलेगी। बाद में इसका विस्तार एससीबी तक किया जाएगा। इसमें कुल 22 स्टेशन होंगे। राजमहल, जयदेव बिहार, कैपिटल हॉस्पिटल, पटिया आदि प्रमुख स्थानों पर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना का निर्माण 2027 तक पूरा किया जाना है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भुवनेश्वर मेट्रो ट्रेन भूमिगत चलेगीः पूर्व मंत्री

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वरः बहुप्रतीक्षित भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर नया अपडेट आया है। राज्य सरकार भुवनेश्वर में पुल के ऊपर की बजाय जमीन के नीचे मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इसकी तैयारियों से संबंधित अधिकांश चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं। भुवनेश्वर मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो ट्रेन की तरह भूमिगत होगी।पूर्व मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना के बारे में मीडिया को जानकारी दी। राजधानी में मेट्रो भूमिगत होगी। मेट्रो भूमिगत चलेगी।

मीडिया को जानकारी देते हुए श्री हरिचंदन ने कहा कि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। भुवनेश्वर में जिस तरह से भीड़ दिन-प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। इसीलिए भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना को भूमिगत बनाने का निर्णय लिया गया है।तत्कालीन सरकार ने भुवनेश्वर में प्रस्तावित मेट्रो रेल की आधारशिला रखी थी। पिछले साल एक जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने त्रिशूलिया के पास रतगढ़ के लेंका साही में आयोजित एक समारोह में मेट्रो रेल की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना पर कुल 6255 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। परियोजना के पहले चरण में यह मेट्रो रेल भुवनेश्वर हवाई अड्डे से त्रिशूलिया चैक तक 26 किलोमीटर तक चलेगी। बाद में इसका विस्तार एससीबी तक किया जाएगा। इसमें कुल 22 स्टेशन होंगे। राजमहल,

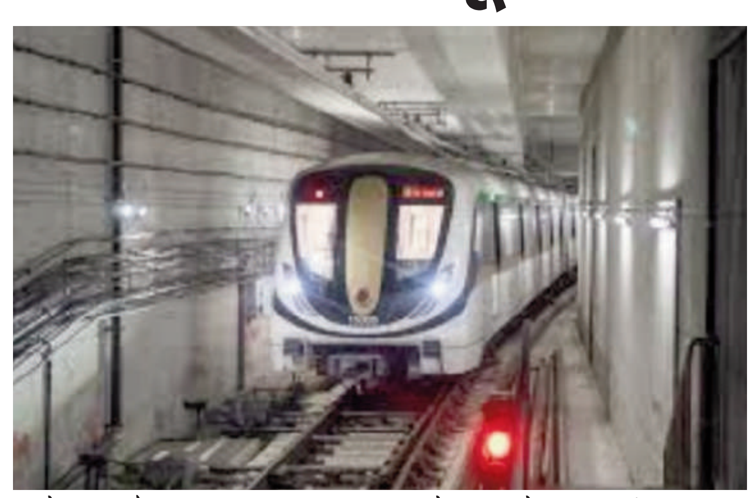

जयदेव बिहार, कैपिटल हॉस्पिटल, पटिया आदि प्रमुख स्थानों पर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना का निर्माण 2027 तक पूरा किया जाना है।

भुवनेश्वर में हाइड्रोजन बसें चलेंगी; पहले चरण में तीन का आयोजन किया जाएगा

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : राजधानी भुवनेश्वर में हाइड्रोजन बसें चलेंगी। सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पहले चरण में तीन बसें परीक्षण के आधार पर चलाई जाएंगी। शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि इस संबंध में शहरी विकास विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।शहरी विकास मंत्री ने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी केन्द्र सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जिस उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने यह योजना बनाई थी, वह पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाई है। इसलिए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महसूस किया है कि स्मार्ट सिटी को कैसे पूरा किया जाए, शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए, शहर का विकास कैसे किया जाए। शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि इसकी योजना बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा स्मार्ट शहरों में प्रदूषण रोकने की भी योजना है। पहले चरण में तीन हाइड्रोजन बसों का परीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हम अपने कृत्यों के प्रति चैतन्य नहीं हैं। हमें लगता है कि हमने अपने सभी क्रिया-कलाप सोच-समझकर/देखभाल कर ही करते हैं।

आश्चर्य होगा यह जानकर कि हम एक काम भी होश में रहकर नहीं करते। कोई हमारी कमजोर नस पर हाथ रख देता है और हम तुरंत वैसे ही व्यवहार/एक्ट करने लगतें हैं। किसी ने गाली दी, हमारा क्रोध उभर आया। किसी ने प्रशंसा की, हम उसके शोषण का शिकार बनने लगे। उदाहरण से समझते हैं, घर में जब बच्चे किशोर होने लगतें हैं तो हार्मोन्स में बदलाव के कारण अपने सौंदर्य के प्रति जागने लगतें हैं, बार-बार आइना देखने लगतें हैं जिसे 'बिगड़ने की स्थिति' जानकर माता-पिता टोकने लगतें हैं। ऐसे में बच्चे को प्रशंसात्मक साथ/स्पर्श की आवश्यकता होती है। बचपन से संभालने/पालने वाले अभिभावक भी उनको सुनना/समझना नहीं कर पाते, तो यही उनके भीतर एक कमजोर नस/घाव बन जाता है। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा, इस कमजोर नस पर ज़रा सा हाथ रख देने भर से, यह बच्चे/किशोर उस अनजान के शोषण का आसान शिकार बन जातें हैं। ऐसा नहीं है कि यह बात सबको पता नहीं है। सबको पता है और सभी अभिभावक अपने जीवन के ऐसे क्षणों/अवस्थाओं से जरूर गुजरे हैं, तब भी वह यह नहीं जान पाते कि अपने बच्चों को इस अवस्था में कैसे साथ/स्पर्श दे पायें? जिससे उनकी इस कमजोर स्थिति का, अनजान/स्वार्थी लोग, लाभ न लें पायें। साथ ही अपनी किशोरावस्था में, अपने हार्मोंस के बदलाव के साथ-साथ, अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकें। केवल भोजन, वस्त्र और जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध करा देने भर से ही माता-पिता/अभिभावकों के कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। यदि हम अपने कृत्यों/व्यवहारों के प्रति चैतन्य नहीं हैं तो हमारे समक्ष होती घटनाओं/स्थितियों/अवसरों के प्रति भी हम बेहोश रहेंगें। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही, अपने समय पर वृक्षों में लग जाते है, उसी प्रकार किये हुए हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्म भी हमारे जीवन में स्वतः ही फल देते रहते हैं। ध्यान रहे कि तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हमारा हृदय है यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र/अवसर/तीर्थ उतने ही हमारे निकट आते चले जायेंगें जिसमें हम स्नान करके नित-नूतन होते चले जायेंगें।

वट सावित्री व्रत आज

सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष स्थान है, जो पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और समृद्धि लाते हैं। इन्हीं विशेष व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत, जिसे विवाहित महिलाएं पूरे श्रद्धा-भाव से अपने पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की सुख-शांति के लिए करती हैं।

हिंदू पंचांग के अनुसार, यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 26 मई को पड़ रहा है। व्रती महिलाएं इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष (बरगद के पेड़) की पूजा करती हैं, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कई बार घर के आस-पास वट वृक्ष मौजूद नहीं होता है।

वट सावित्री व्रत की तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन अगले दिन यानी 26 मई को सुबह 08 बजकर 31 मिनट पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा।

पूजा विधि

सुबह जल्दी उठें स्नान करें और पूजा घर की सफाई करें।

इस व्रत में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व होता है।

बरगद के पेड़ के नीचे साफ-सफाई करें और मंडप बनाएं।

वट वृक्ष के नीचे सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें।

सावित्री और सत्यवान की पूजा करें, और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं।

लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें।

व्रत कथा का पाठ करें या सुनें और अंत में आरती करें।

गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद लें।

व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें।

वट वृक्ष की पूजा का महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवनदान दिलवाया था। तभी से इस वृक्ष की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस वृक्ष की पूजा विधिपूर्वक की जाए।

बरगद का पेड़ पास में न हो तो क्या करें?

आज के समय में खासकर शहरी क्षेत्रों में वट वृक्ष हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। यदि आपके आस-पास बरगद का पेड़ नहीं है, तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की एक टहनी मंगवा सकती हैं। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन किया जा सकता है। ऐसा करने से भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है।

कम से कम इतनी बार करना चाहिए खाटू श्याम के दर्शन, रोज होती है बाबा की श्रृंगार आरती

अनन्या मिश्रा

कहा जाता है कि कोई भी भक्त बाबा श्याम के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। रोजाना देश भर से हजारों भक्त बाबा श्याम के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में कम से कम कितनी बार जाना चाहिए। बाबा खाटू श्याम को कलियुग का हारे का सहारा कहा जाता है। राजस्थान जिले के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जिसके पट पूरे 24 घंटे खुले रहते हैं। मंदिर में दिन में 5 बार आरती होती है। वहीं इस मंदिर की खासियत है कि यहां पर रोजाना बाबा श्याम का विशेष तौर पर श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी भक्त बाबा श्याम के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। रोजाना देश भर से हजारों भक्त बाबा श्याम के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में कम से कम कितनी बार जाना चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा श्याम की कितनी बार आरती होती है।

कब और कितनी बार होती है आरती

बाबा खाटू श्याम जी की पहली आरती गर्मी में सुबह 04:30 बजे और सर्दियों में 05:30 बजे होती है। वहीं मंगला आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आरती से पहले बाबा का विशेष फूलों से श्रृंगार किया जाता है और फिर आरती और भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। सुबह की वजह से इसको श्रृंगार आरती भी कहा जाता है। इस आरती का समय सुबह 07:00 बजे होती है।

वहीं तीसरी आरती दोपहर 12:30 मिनट पर होती है। इस दौरान बाबा को गाय की दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। वहीं संध्या आरती सूर्यास्त के बाद की जाती है। गर्मियों में संध्या आरती सुबह 07:30 मिनट पर और सर्दियों में आरती शाम को 06:30 मिनट पर की जाती है। ग्यारस के दौरान बाबा श्याम का दरबार 24 घंटे खुला रहता है।

कितनी बार करें बाबा के दर्शन

वैसे तो आप जितनी बार चाहें, उतनी बार बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मन्नत या विनती करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है आपको कम से कम तीन बार खाटू श्याम के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि बाबा खाटू श्याम को तीन बाण धारी कहा जाता है। यदि आप बहुत परेशान हैं, तो पहले दर्शन में अपनी अर्जी लगाएं। फिर दूसरी बार बाबा से विनती करें और तीसरी बार में आप भक्त और भगवान की तरह बाबा से बात और बहस कर सकते हैं।

रोजाना गौ माता की आरती करने से पुण्यफल की होती है प्राप्ति, बढ़ती है धार्मिकता

अनन्या मिश्रा

अगर रोजाना गाय की सेवा करना संभव नहीं है, तो ऐसे में रोजाना गाय की आरती जरूर करनी चाहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा-अर्चना के बाद गाय की आरती जरूर करनी चाहिए। इससे जातक को कई लाभ प्राप्त होंगे।

सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। वहीं शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय एक मात्र ऐसा पशु है, जिसमें सभी देवी-देवताओं का वास होता है। ऐसे में गाय की पूजा-अर्चना करने से न सिर्फ गौ माता बल्कि सभी देवी-देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही हर तरह के दोष भी दूर हो जाते हैं। वहीं अगर रोजाना गाय की सेवा करना संभव नहीं है, तो ऐसे में रोजाना गाय की आरती जरूर करनी चाहिए।

आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा-अर्चना के बाद गाय की आरती जरूर करनी चाहिए। इससे जातक को कई लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको गौ माता की आरती के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही इसके लाभ के बारे में भी जानेंगे।

गाय की आरती

ॐ जय गौ माता, मैया जय धेनु माता। मुकुन्द विधाता उमापति, सीतापति ध्याता।। ॐ जय धेनु माता

सागर मंथन उपजी, कामधेनु माता। नमन किए सब देवता, अति पावन नाता।। ॐ जय धेनु माता

तनुजा जो तुझसे जन्मी, नंदिनी नाम रचे। ऋषि वशिष्ठ की शक्ति, राजा दिलीप भजे।। ॐ जय धेनु माता

पाप विनाशिनी मैया, सुखद भंडार भरे। तैंतीस कोटि दैवत, अंग निवास करे।। ॐ जय धेनु माता

पंचगव्य है पावन, औषध गुणकारी। रोग दोष मिटाए, मॉ तुम उपकारी।। ॐ जय धेनु माता

जिस घर अंगना धेनु, माँ की हो सेवा। वैतरणी तरते वो नर, पाते शुभ मेवा।। ॐ जय धेनु माता

शुभ मति शुभ फल दायक, है संकट त्राता। जो जन करते सेवा, मोक्ष सुफल पाता।। ॐ जय धेनु माता

आरती वंदना धेनु की, जो नर हैं गाते। कहते हैं श्रीकृष्णा, वे मनु तर जाते।। ॐ जय धेनु माता

गाय की आरती के लाभ

बता दें कि रोजाना गौ माता की आरती करने से जातक में धार्मिकता बढ़ती है और उसको आध्यात्म की प्राप्ति होती है।

रोजाना गौ माता की आरती करने से जातक के पुण्य में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है।

गौ माता की रोजाना आरती करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है।

इससे ग्रह दोष और वास्तु दोष भी नष्ट होता है। साथ ही पितृ दोष भी दूर होता है।

रोजाना गौ माता की आरती करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही सकारात्मकता और संपदा का भी आगमन होता है।

वहीं रोजाना गाय की आरती करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है और जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

पति-पत्नी के बीच कलेश को खत्म करने के लिए इन मंदिरों में करें दर्शन, भक्तों की लगती हैं भीड़

आज हम आपको भारत के उन चार मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि यहां पर यदि पति-पत्नी आते हैं। तो दर्शन मात्र से उनके जीवन का कलेश दूर हो जाता है। इसलिए इन मंदिरों में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में सुख-संपन्नता आती है। भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं, जहां की अलग-अलग मान्यताएं हैं। देश में कुछ ऐसे खास मंदिर हैं, जिनकी पौराणिक मान्यताओं की वजह से सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। फिर चाहे त्योहार हो या फिर ऑफ सीजन हो। इन मंदिरों में कभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको भारत के उन चार मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि यहां पर यदि पति-पत्नी आते हैं। तो दर्शन मात्र से उनके जीवन का कलेश दूर हो जाता है। इसलिए इन मंदिरों में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में सुख-संपन्नता आती है।

रणथंभोर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभोग का त्रिनेत्र गणेश मंदिर तब सुर्खियों में आया जब बॉलीवुड कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ अपनी शादी से पहले इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। माना जाता था कि मंदिर को पहला शादी का निमंत्रण भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां पर हिंदू देवता की मूर्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्थापित है। यह इस क्षेत्र का सबसे प्रचीन मंदिरों में से एक है। जिसका इतिहास सदियों पुराना है। मान्यता है कि जो भी जोड़े यहां दर्शन के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी के कलेश कम हो जाते हैं।

तिरुपति मंदिर तिरुपति मंदिर भी उन जोड़ों को भी आकर्षित करता है, जो शादी करना चाहते हैं या फिर शादी के बाद खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। साल 2017 में मंदिर बोर्ड ने एक अनोखी पहल शुरू की। जिसमें जोड़े डाक द्वारा भगवान तिरुपति को निमंत्रण पत्र देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मंदिर के अधिकारी जोड़े को थालंब्रालु भेजतें हैं, जोकि आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। बता दें कि यह निशुल्क सेवा है और नवविवाहितों द्वारा भी लाभ उठाया जाता है। ऐसे में अगर आपके शादीशुदा जीवन में कलेश है, तो एक बार आपको इस मंदिर में आकर दर्शन करना चाहिए।

गुरुवायुर मंदिर केरल के गुरुवायुर मंदिर में दुनियाभर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। जिसमें कई जोड़े भी शामिल होते हैं। सबसे पहले जोड़े यहां आकर शादी से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। यह मंदिर एक पसंदीदा विवाह स्थल भी बना हुआ है। माना जाता है कि जो भी जोड़ा यहां शादी करता है, उसको लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है।

कहीं विनाश का कारण ना बन जाएं हीट रिस्क का फैलाव

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

हीट रिस्क के बढ़ते दायरे को देखते हुए आज हीट एक्शन प्लान बनाये जाने लगे हैं। हांलाकि कि यदि केवल सामान्य नागरिकों के बढ़ती गर्मी के कारण होने वाले प्रभाव पर ही बात की जाए तो गर्मी बीमारियों का प्रमुख कारण बनती जा रही है।

जलवायु परिवर्तन की दुश्वारियों में से एक देश और दुनिया के देशों में हीट रिस्क के व्यापक प्रभाव से आसानी से समझा जा सकता है। यदि हम भारत की ही बात करें तो 2011 से 2022 के दशक के अध्ययन के अनुसार देश में हीट रिस्क का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया है। मजे की बात यह है कि अब दिन की तुलना में रातें भी अधिक गर्म होने लगी है। इसका एक बड़ा कारण आज की भवन निर्माण विधि और शहरों में कंक्रिट का जंगल विकसित होना और अन्य के साथ ही इलेक्ट्रोनिक उत्पाद खासतौर से अत्यधिक उर्जा खपत वाले फ्रीज और कूलर की जगह लेते एयरकण्डीशनर भी एक है। घटते जंगल और आबादी का दबाव भी एक बड़ा कारण है। ऊर्जा के रुप में जो संसाधान उपयोग किये जा रहे है वे भी जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक बन रहे हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एण्ड वॉटर सीईईडब्ल्यू की हालिया रिपोर्ट अत्यधिक चिंतनीय और हालात की गंभीरता को दर्षाती है। रिपोर्ट की माने तो देश की तीन चौथाई आबादी आज हीट रिस्क की जद में आ चुकी है। देश के 734 जिलों में से 417 जिले तो अत्यधिक जोखिम वाले जिलों में शुमार हो चुके हैं। कम जोखिम वाले जिलों में तो केवल और केवल 116 जिले ही रह गये हैं।

हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि वैसे तो हीट रिस्क के दायरें में नोर्थ ईस्ट और उत्तरी भारत के नाममात्र के क्षेत्र को छोड़ दिया जाये तो समूचा देश आज हीट रिस्क के दायरें में आ चुका है। देश के 10 जिले राजस्थान, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश हीट रिस्क की अत्यधिक जद में आये प्रदेश व केन्दशासित राज्य है।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही हीट रिस्क का दायरा बढ़ रहा है। अपितु अब यह वैश्विक समस्या हो चुकी है। दुनिया के देशों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी की तपन से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। जंगलों में दावानल और बैमौसम आंदि तूफान, सूखा या बाढ़ ऐसी समस्यायें आने लगी है जिससे साल दर साल अब अधिक दोचार होना पड़ रहा है। अमेरिक का फर्नेस क्रीक सबसे अधिक गर्म स्थान है तो ट्यूनिशिया का केबिली, कुवैत का मित्रिबाह, ईरान का अहबाज और लुट रेगिस्तान, चीन का फ्लेमिंग आदि स्थान ऐसे है जो सर्वाधिक गर्मी वाले स्थान है। इसके साथ ही मौसम के मिजाज में भी बदलाव आया है। सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्द रात जैसे व असमय आंधी बरसात आम होती जा रही है। गर्मी के दिन बढ़े है। फरवरी तक अब अपनी परंपरागत मौसम का दायरा छोड़ते हुए अत्यधिक गर्मी वाले महीनों में से एक होने लगा है। आखिर यह मौसम का बदलाव भावी संकट की और साफ साफ इशारा कर रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। समुद्र किनारे के शहरों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अब डूबने का ड़र

सताने लगा है। अमेरिका ही नहीं दुनिया के अन्य देशों के जंगलों में जिस तेजी से आग की घटनाएं बढ़ रही है वह अपने आप में अलग चुनौती होती जा रही है। बीमारियों का असर बढ़ रहा है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं।

हीट रिस्क के बढ़ते दायरे को देखते हुए आज हीट एक्शन प्लान बनाये जाने लगे हैं। हांलाकि कि यदि केवल सामान्य नागरिकों के बढ़ती गर्मी के कारण होने वाले प्रभाव पर ही बात की जाए तो गर्मी बीमारियों का प्रमुख कारण बनती जा रही है। कई मिलियन मौतों का कारण हीट वेव है। निर्जलीकरण तो एक प्रमुख कारण है ही इसके साथ ही कार्डियोरेस्पिरेटरी के मामलें आम होते जा रहे हैं। अनिद्रा, तनाव, श्वासं लेने में परेशानी, दस्त, पेट दर्द, फूड पोइजनिंग और तापघात आदि बीमारियों का प्रकोप लूताप के कारण दुनिया के देशों में बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से हीट रिस्क का विस्तार होता जा रहा है उससे आने वाले समय में और अधिक गंभीर हालातों का सामना करना पड़ेगा। किसी समय भारतीय परंपरा के अनुसार नौतपा ऐसा समय होता था जब सबसे अधिक गर्मी पड़ती थी। यह भी माना जाता था कि जितना अधिक नौतपा प्रभावी रहेगा उतना ही अच्छी बरसात होगी। पर आजकल यह सारे कंसेप्ट बेमानी होते जा रहे हैं नौतपा के पहले ही इतना तप चुका होता है कि एक एक दिन निकालना भारी हो जाता है। इसके साथ ही कही ना कही गर्मी मौत का या विनाश का कारण ना बने इसके बारे में वैज्ञानिकों को गंभीर मंथन करना होगा। जिस तरह से आज हमारे घर ही तापमान की बढ़ोतरी का कारण बनते जा रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्यावरण सहयोगी साधन खोजने होंगे। पहले मकानों में चूने का उपयोग होता था तो दीपावली पर कली भी चूने की होती थी पर आज सारे हालात बदल गए हैं। एक तो गगनचुंबी इमारते और फिर उसका निर्माण लोहे सीमेंट से और इसके साथ ही दैनिक उपयोग के तापमान बढ़ाने वाले सामानों, उपकरणों के उपयोग के चलते बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने की बात करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसें में गर्मी के कारण चौराहों पर हरी पट्टी तान देने या सड़कों पर पानी का छिड़काव करना कोई समाधान नहीं हो सकता बल्कि वैज्ञानिकों और नीति नियंताओं को गंभीर चिंतन करते हुए समय रहते हुए तापमान की बढ़ोतरी के कारकों को नियंत्रित करने के उपायों पर ठोस प्रयास करना होगा।

एमसीडी के पार्कों में दौर रहा मौत का 'करंट', प्रशासन बेखबर

सुषमा रानी

दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में एक पार्क में करंट लगने से बच्चे की मौत के बाद भी एमसीडी की लापरवाही जारी है। पार्कों में नंगे तार खुलेआम घूम रहे हैं जिससे खतरा बना हुआ है। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे लोगों में डर का माहौल है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

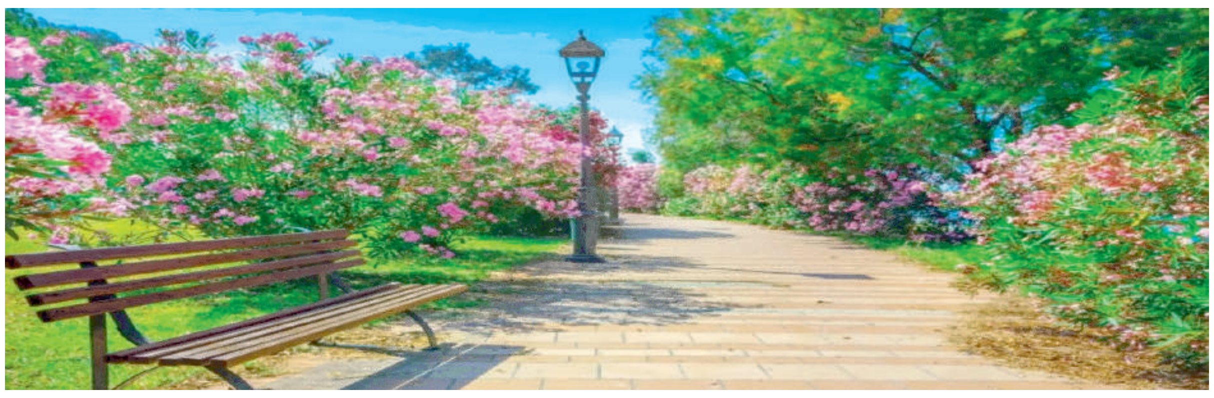

दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी थाना क्षेत्र के महर्षि दयानंद पार्क में करंट लगने से नौ वर्षीय बच्चे की मौत के बाद भी विभाग पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जिस पार्क में घटना हुई, वहां पिछले एक माह से स्ट्रीट लाइट के खंभे का तार कटा हुआ है। इस खतरनाक हिस्से की ऊंचाई करीब ढाई फीट है। यानी कोई भी बच्चा खेलते समय इसे छू सकता है।

आरडब्ल्यूए की शिकायत के बाद भी अभी तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। आसपास के एमसीडी पार्कों का भी यही हाल है। हादसे के मद्देनजर जागरण टीम ने रविवार को आसपास के पार्कों में खंभों की स्थिति की पड़ताल की तो इसमें चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिले। एमसीडी के अधिकतर पार्कों में नंगे तार खंभों को छू रहे हैं। बारिश होने पर करंट खंभे के साथ-साथ जमीन में भी उतर सकता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

महर्षि दयानंद पार्क

कालकाजी डीडीए फ्लैट्स एल-वन ब्लॉक स्थित इसी पार्क में 24 मई की शाम करंट लगने की घटना हुई थी। इस छोटे से पार्क में एक तरफ बैडमिंटन कोर्ट है तो दूसरी तरफ झूले हैं। इसके पीछे बीएसईएस का बॉक्स लगा है। ढाई फीट की दूरी पर स्ट्रीट लाइट का खंभा है।

खंभे के बेस पर लगे तार कटे हुए हैं। गेट के बगल और शेड के पास लगे खंभे का भी यही हाल है। सुबह-शाम बच्चे वहां खेलते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आरडब्ल्यूए ने कई बार एमसीडी और बीएसईएस से शिकायत की। हद तो यह है कि हादसे के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई।

बुद्ध वाटिका

यह पार्क भी एल-1 ब्लॉक में है। इसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। झूले टूट चुके हैं। कूड़े का ढेर लगा है। गेट के पास स्ट्रीट लाइट लगी है। रहवासियों के मुताबिक, यह भी ठीक से काम नहीं करती। खंभे के नीचे तीन-चार फटे तार बेतरतीब ढंग से लगे हुए हैं।

नंगे तार खुले हैं और लोहे के खंभे को छू रहे हैं। रखरखाव ठीक न होने के कारण यहां बच्चे कम ही आते हैं। ज्यादातर समय यहां सन्नाटा रहता है। ऐसे में अगर कोई बच्चा यहां आ जाए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

संतोषी माता मंदिर पार्क

मंदिर के सामने इस पार्क के आसपास बाजार है। यहां बैडमिंटन कोर्ट और बच्चों के लिए झूले लगे हैं। दोपहर में कई किशोर बैडमिंटन खेल रहे थे।

गेट से पार्क में घुसते ही हमारी नजर स्ट्रीट लाइट के खंभे पर पड़ी। बेस पर तार में कई जोड़ थे, जिन्हें टेप से चिपकाया गया था। लेकिन कई जोड़ खुले थे। आस-पास खेल रहे किशोर इस बात से अनजान अपने काम में व्यस्त थे।

दिल्ली विवेक विहार अस्पताल अग्निकांड, एक साल बाद भी न्याय का इंतजार; 7 बच्चों की मौत का मामला

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक साल पहले बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से सात नवजात शिशुओं की जान चली गई थी। पीड़ितों के परिवार अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरोपी डॉक्टरों को जमानत मिल गई है जिससे पीड़ितों में निराशा है। अस्पताल अब खंडहर में बदल चुका है और एसीबी की जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं।

पूर्वी दिल्ली। विवेक विहार में अवैध रूप से संचालित बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत को एक साल हो गया है। उन नवजात बच्चों के परिजनों की आंखें न्याय के इंतजार में पथरा रही हैं। अपने मासूम बच्चों को खो चुकी माताएं आज भी सिसकियां भर रही हैं। आरोपी अस्पताल संचालक डॉ. नवीन खीची और हादसे के वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत के मामले में मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए। आरोपियों को सजा मिलने पर ही उन्हें न्याय मिलेगा।

जिस अस्पताल में आग लगी है, वह खंडहर हो चुका है। बाहर टीन के शेड लगे हैं। यहां के स्थानीय लोग आज भी उस घटना को याद कर सहम जाते हैं।

पीड़ित परिवारों का कहना है कि वह कभी नहीं भूल सकते कि हादसा कितना भयानक था। वह नवजात बोल नहीं सकते थे और हादसे के वक्त उनके साथ कोई परिजन भी नहीं था। जब वह अस्पताल पहुंचे तो उनके शव देखकर उनकी सांसें थम गईं। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द दोनों आरोपी डॉक्टरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पैसों के लालच में अस्पताल संचालक बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चला रहा था। वह पांच बेड की अनुमति लेकर 20 से 25 मरीजों को भर्ती कर रहा था। बता दें कि 26 मई 2024 को शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लग गई थी, सात नवजात जलकर मर गए थे। बेबी केयर न्यू अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद दिल्ली के एलजी ने एसीबी को अस्पतालों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। एसीबी ने तीन महीने में 146 अस्पतालों और नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में एसीबी को अस्पतालों में कई खामियां मिलीं।

मदनगीर मंडल में तिरंगा यात्रा निकाल कर सेना के पराक्रम को लोगों ने किया सलाम

'ऑपरेशन सिंदूर' हमारे वीर सैनिकों की अदम्य शौर्य गाथा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक : रमेश बिधूड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मदनगीर मंडल अंबेडकर नगर में ऑपरेशन सिंदूर के निमित भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को नमन करते हुए भारतीय सेना के सम्मान में 'तिरंगा यात्रा' आयोजित की गई।जिसमें दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने शामिल होकर सभी को संबोधित किया तथा माँ भारती के वीर सपूतों को नमन किया।

'ऑपरेशन सिंदूर' हमारे वीर सैनिकों की अदम्य शौर्य गाथा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह तिरंगा यात्रा न केवल देशभक्ति का उत्सव है, बल्कि हर भारतवासी के हृदय में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सुदृढ़ करती है।इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए मेरे सभी साथियों, संस्थाएं, सामाजिक संगठन, आरडब्ल्यूए, धार्मिक संगठन आदि ने सहयोग किया। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने सभी तरह के भेदभाव को भूलकर सेना के शौर्य एवं पराक्रम को सलाम किया, वहीं यह भी साबित किया कि भारत की जनता राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार है। भारत की सेना विश्व की सबसे काबिल एवं ताकतवर सेना है जो दुश्मनों के किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्यवाई से पूरे देश में उत्साह एवं खुशी की लहर है, इसी के तहत मदनगीर मंडल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई।

केजरीवाल सरकार जलभराव होने पर अधिकारियों पर दोषारोपण कर दिल्ली वालों को भाग्य भरोसे छोड़ देती थी : वीरेन्द्र सचदेवा

सुषमा रानी

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की दिल्ली में हर वर्ष ओचक आंधी तूफान आने की घटनाएं होती रही हैं और साथ ही मानसून में जलभराव की भी पर गत वर्ष तक ऐसे दिनों पर तत्कालीन सरकार की लापरवाही के चलते दिल्ली की दुर्दशा देखते बनती थी पर वही स्थिती आज बहुत सुधर चुकी है।

सचदेवा ने ने कहा है की आज सुबह जब दिल्ली वाले जागे तो कल देर रात आये तूफान के चलते दिल्ली में अनेक स्थानों पर पेड़ गिरने एवं जल भराव आदि की शिकायतें सामने थीं।

दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी भाजपा विधायको एवं पार्षद, जलबोर्ड एवं लोकनिर्माण विभाग अधिकारी रविवार होने के बावजूद सड़कों पर उतरे और सुबह 9 बजने तक दिल्ली की सड़कों से पेड़ हटा कर एवं अधिकांश जलभराव साफ करवा कर दिल्ली का यातायात सुगम किया और दोपहर12 बजने तक स्थिती को सामान्य बना दिया।

हर बरसात के बाद दिल्ली की जनता को तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार एवं वर्तमान भाजपा सरकार में अंतर साफ दिख रहा है।

सचदेवा ने कहा है की जहां केजरीवाल सरकार जलभराव होने पर उपराज्यपाल एवं अधिकारियों पर दोषारोपण कर दिल्ली वालों को भाग्य भरोसे छोड़ देती थी वहीं वर्तमान भाजपा सरकार जिम्मेदारी खुद पर लेती है और आकसमिक तूफान बरसात के बाद स्थिती सामान्य करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मियों को अपनी शक्ति बनाती है।

सेक्टर 1 पॉकेट 1 द्वारका में हाउस टैक्स एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सेक्टर 1 पॉकेट 1 द्वारका आरडब्ल्यूए के सौजन्य से निशुल्क हाउस टैक्स कैंप एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। हेल्थ चेकअप कैंप में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के अनुभवी एवं योग्य चिकित्सकों द्वारा लोगों की विभिन्न बीमारियों का इलाज किया गया तथा उन्हें आवश्यक परामर्श दिए गए। वही पॉकेट के लोग सुविधाजनक ढंग से अपना हाउस टैक्स भर सके इसके लिए हाउस टैक्स कैंप का आयोजन भी किया गया। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एडवोकेट हरीचंद जाखड़ ने वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के चेयरमैन राजपाल सोलंकी का आभार व्यक्त किया जिनका जीवन हमेशा समाज के प्रीति समर्पित रहा है जिन्होंने इस हेल्थ चेकअप कैंप के आयोजन में अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल एक ख्याति प्राप्त अस्पताल है जहां देश दुनिया के मरीज अपनी चिकित्सा कराने के लिए आते हैं। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए यहां अनुभवी डाक्टर हैं जो मरीजो को बेहतर चिकित्सा प्रदान करते है। आरडब्ल्यूए के अन्य पदाधिकारी ने भी कैंप के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी एवं सक्रियता दिखाई, जिसमें प्रमोद कौशिक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ए.वी बख्शी, उपाध्यक्ष, पीसी त्रिपाठी, महासचिव, अतर सिंह, सचिव, नितिन मित्तल, खजांची, एसवी रमण, पूर्व महासचिव, अरुण शर्मा, नवेदिता, मनोज कुमार, वीके सुमन, महासचिव (एससीडब्ल्यूए) प्रेसिडेंट श्री जाखड़ ने खासतौर पर पीसी त्रिपाठी, एवी बख्शी, एसवी रमण, अतर सिंह की सेवाओ को आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हरीचंद जाखड़ ने बहुत सरहाना की जिनके सुपरविजन में कैम्प ने काम किया। उन्होंने सभी चिकित्सकों अपने पदाधिकारी एवं पॉकेट के लोगों का आभार व्यक्त किया जो हमेशा इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाकर सफल बनाते हैं।

देश में कोरोना की फिर से वापसी, डरने की जरूरत नहीं सतर्कता बरतें

मुख्य संवाददाता,/सुषमा रानी

दिल्ली: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में कोरोना के दिल्ली से 23, हरियाणा से 5, गुजरात से 33 और महाराष्ट्र से 56 एक्टिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश से 4, कर्नाटक से 16, केरल से 95, तमिलनाडु से 66, पुडुचेरी से 10, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से कोरोना के एक-एक मामले सामने आए हैं। इसी बीच दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के हिसाब से कोरोना के एक्टिव मामले बहुत कम हैं। ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण देखने को मिले हैं और उन्हें में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ज्यादातर एक्टिव केस में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड की नई लहर का कोई संकेत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है।

"फन वे लर्निंग एनजीओ द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय ए 142 फतेह नगर में होम्योपैथी मेडिसिन कैंप का किया गया आयोजन

प्राधिकरण पर किसानों की अनदेखी का आरोप, महापंचायत कर जताई नाराजगी

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों ने रबूपुरा में महापंचायत की जिसमें उन्होंने प्राधिकरण पर अनदेखी का आरोप लगाया। किसान कल्याण परिषद के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में किसानों ने मुआवजे रोजगार और आवास जैसी समस्याओं पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने 20 जून तक मांगें पूरी न होने पर निर्माण कार्य रोकने की चेतावनी दी। प्राधिकरण किसानों की बेशकीमती जमीनों को बेहद कम दामों पर खरीद रहा है।

रबूपुरा। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों ने रविवार को सेक्टर 29 स्थित तिरथली गांव में महापंचायत का आयोजन किया।किसान कल्याण परिषद के नेतृत्व में आयोजित महापंचायत में प्राधिकरण क्षेत्र के 31 गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया।पंचायत में किसानों ने प्राधिकरण पर किसानों की अनदेखी करने और उनकी समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाया।

महापंचायत में किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने कहा कि विकास के नाम पर प्राधिकरण किसानों की बेशकीमती जमीनों को बेहद कम दामों पर खरीद रहा है। किसान दर-दर भटकने को मजबूर हैं। प्राधिकरण की गलत नीतियों के कारण अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को आवास, रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क आदि से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिषद के महामंत्री सुशील शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण ने 16 साल पहले क्षेत्र के कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक न तो अधिग्रहण के बदले किसानों को मिलने वाले 7 प्रतिशत आबादी के भूखंड दिए गए और न ही पुरानी आबादी की समस्या का समाधान हो सका।

परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। रिंकू भाटी ने कहा कि अधिग्रहण के समय प्राधिकरण को गांवों में नाली, चकरोडों, चारागाह आदि के लिए हजारों बीघा जमीन मुफ्त में मिली थी। इसके बदले में भूमिहीन गरीब मजदूरों को 100 वर्ग गज के भूखंड मुफ्त दिए जाएं।

उदयवीर सिंह ने कहा कि प्राधिकरण को एयरपोर्ट की तरह सभी विस्थापितों को आबादी भूखंड देने चाहिए।किसानों ने कहा कि यदि 20 जून तक उनकी सभी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे।

सुकोफिट एंड कीर्तन फाउंडेशन ने किया सिविल डिफेंस मथुरा को सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा: जिला अधिकारी नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के आदेश अनुसार दिनांक 25 मई 2025 को प्रातः 5:30 बजे सुकोफिट एंड कीर्तन फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा कराई गई दस किलोमीटर, पांच किलोमीटर एवं तीन किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा के द्वारा सिविल डिफेंस मथुरा के 70 वार्डन एवं स्वयंसेवक को ड्यूटी लगाई गई जिसमें उप नियंत्रक सुमित मौर्य के नेतृत्व मे पोस्ट वार्डन अशोक यादव की क्विक रिस्पांस टीम एवं सिविल डिफेंस के वार्डन एवं स्वयंसेवकों ने वात्सल्य ग्राम वृंदावन से लेकर अग्रसेन चौक तक जगह जगह पर वैरिकेटिक करके यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करते नजर आए साथ ही दौड़ने वाले प्रतियोगियों को जूस एवं पानी दिया गया। बही संस्थान की पदाधिकारी डॉक्टर संगीता सिंह ने सिविल डिफेंस मथुरा की तरफ से पोस्ट वार्डन अशोक यादव एवं राम कुमार चौहान जी के साथ उनकी पूरी टीम को मेडल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया जिसकी सिविल डिफेंस मथुरा के चीफ वार्डन राजीव अग्रवाल डिप्टी चीफ वार्डन कल्याण दास अग्रवाल डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी डिप्टी डिविजनल वार्डन राजेश कुमार मित्तल सीनियर स्टाफ ऑफीसर दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की ड्यूटी पर डिप्टी पोस्ट वार्डन त्रिवन चन्द यादव, सेक्टर वार्डन राम सैनी, गोविंद, गुलशेर, मुकेश, देवेन्द्र, रोहित, राजेश, हेमंत, चरन सिंह, शैलेश, सुनेन राजेंद्र, विवेक, विक्रम, जितेन्द्र कुमार धनगर, सोहन लाल कौशिक, श्याम बाबू, रोहताश, सूरज सरकार, नरेंद्र, लड्डु गोपाल, जयवीर, अरुण यतेंद्र आदि वार्डन एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

बिजली निगम के लिए 4696 करोड़ रुपये की वसूली चुनौती, कैसे होगा निपटारा?

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं पर 4696 करोड़ रुपये बकाया है जिसकी वसूली निगम के लिए एक चुनौती है। निगम ने 11 नवंबर तक सरचार्ज माफी योजना शुरू की। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर छूट और ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। पहली बार यह योजना सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है जिसमें किश्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है।

बादशाहपुर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बिजली उपभोक्ताओं पर 4696 करोड़ रुपये बकाया है। यह राशि वसूलना बिजली निगम के लिए बड़ी चुनौती है।

इस राशि की वसूली के लिए बिजली निगम ने 11 नवंबर तक सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इसमें से 2582 करोड़ रुपए ऐसे उपभोक्ताओं पर बकाया है, जिनके बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। 11,79,583 उपभोक्ताओं पर 4696 करोड़ रुपए बकाया है। इन 11.79 लाख उपभोक्ताओं में से 3,63,047 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं।

बिजली निगम ने पहली बार सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। योजना 12 मई से शुरू की गई है। इस बार बिजली निगम प्रबंधन ने सभी अधिकारियों को बकाया बिजली बिल राशि वसूलने के सख्त निर्देश दिए हैं। इससे पहले बिजली निगम ने सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की थी।

सरचार्ज माफी के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट

बिजली बिल बकायादार उपभोक्ता यदि बकाया बिल का निशुल्क भुगतान करते हैं तो सभी पात्र घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सम्पूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तिथि तक कुल विलम्ब भुगतान अधिभार माफ किया जाएगा।

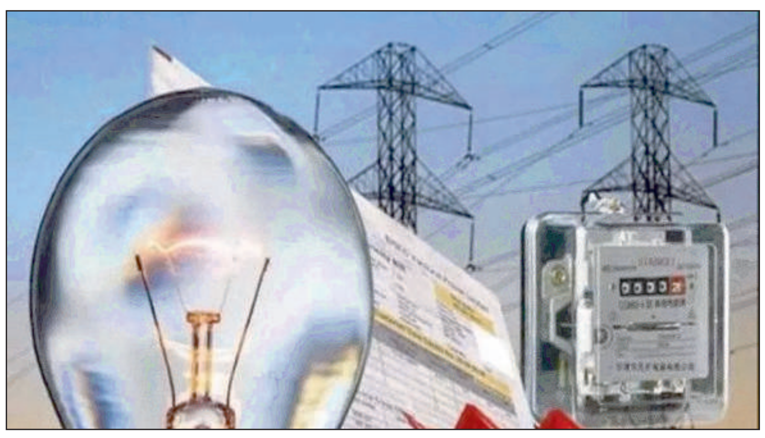

योजना में भाग लेने का निर्णय लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि एकमुश्त या आठ मासिक या चार द्विमासिक किस्तों में चुकाने का विकल्प मिलेगा। बकाया ब्याज राशि आठ चालू मासिक या चार द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ कर दी जाएगी।

औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए कुल मूल राशि का 50 प्रतिशत तथा अधिभार राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी।

केस वापिस लेने वाले उपभोक्ता भी उठा सकते है लाभ

गलत बिलिंग के मामलों को विद्युत निगम के निर्देशानुसार ठीक कराया जाए। जिन उपभोक्ताओं के मामले बिलिंग विवाद के कारण वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में लंबित हैं, वे अपना मामला वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मामला वापस लेने वाला उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा। सभी श्रेणियों के डिफॉल्टर उपभोक्ता समय से पहले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ब्याज माफी योजना 2025 लागू है। इस बार योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

-ए श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

कानपुर में जीएसटी में फिर मारा रिमझिम स्पात पर छापा : छानबीन जारी, हड़कंप

सुनील बाजपेई

कानपुर। कर चोरी के मामले में रिमझिम इस्पात में जीएसटी की छापे का दौर जारी है।जिसके क्रम में शनिवार की रात शुरू किया गया छापा आज रविवार को भी जारी रहा।

बताया गया कि 2 माह में दूसरी बार रिमझिम इस्पात पर स्टेट जीएसटी की टीमों ने छापेमारी की है।

याद रहे कि इससे पहले फरवरी माह में आयकर विभाग की टीमों ने कार्रवाई की थी। यह छापेमारी कानपुर समेत 4 शहरों में स्थित कंपनी की फैक्ट्री और ऑफिस में की गई है।

टैक्स चोरी समेत तमाम वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत पर की गई कार्रवाई रविवार सुबह भी जारी रहा। विभागीय अधिकारियों ने कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की बात स्वीकारी है। हालांकि आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

स्टेट जीएसटी सूत्रों के मुताबिक इस्पात कंपनी के कानपुर स्थित फजलगंज, आजाद नगर समेत आधा दर्जन ठिकानों पर शनिवार देर रात एस जीएसटी की टीमें ने एक साथ पहुंची। सूत्रों के अनुसार हमीरपुर के भरूवा सुमेरपुर स्थित फैक्ट्री में सबसे पहले शनिवार सुबह टीम पहुंची थी।

छापेमारी में लगे अधिकारियों के अनुसार, बड़े स्तर पर टैक्स चोरी के अलावा अधिक मुनाफा होने की जानकारी छिपाना, बोगस पर्चों पर कारोबार करने समेत कई वित्तीय धांधली सामने आई हैं।

सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मामले में विभाग को करना पड़ रहा परेशानी का सामना करना पड़ा। विभाग आज रविवार को भी सभी ठिकानों पर दस्तावेजों संग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जांच पड़ताल में लगा रहा। इसके फलों स्वरूप कल चोरी में माहिर उद्योगों में भी हड़कंप देखा गया।

गाजियाबाद में जल्द शुरू होगा दूसरा पशु जन्म नियंत्रण केंद्र, हर दिन इतने कुत्तों की होगी नसबंदी

गाजियाबाद नगर निगम का दूसरा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर जून से शुरू होगा जहां प्रतिदिन 40 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए निगम तीन एबीसी सेंटर चलाएगा। नए बस अड्डे के पास बने सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है और सिद्धार्थ विहार के पास तीसरा सेंटर बन रहा है। सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी।

गाजियाबाद। नगर निगम के दूसरे एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का काम पूरा हो गया है। जून से यहां कर्मचारियों की तैनाती कर कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अनुज ने बताया कि यहां प्रतिदिन 40 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी।

कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए निगम शहर में तीन एबीसी सेंटर संचालित करेगा। पहला एबीसी सेंटर नंदग्राम में चल रहा है जबकि नए बस अड्डे के पास दूसरे सेंटर का काम पूरा हो चुका है। इसकी कार्यदायी संस्था जल निगम है।

इसी माह एबीसी सेंटर जल निगम से नगर निगम को हस्तांतरित हो जाएगा। इसके बाद अगले माह एबीसी सेंटर का उद्घाटन कर उसे शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम का तीसरा एबीसी सेंटर सिद्धार्थ विहार के पास बन रहा है। इसका काम भी तेजी से चल रहा है।

करीब तीन माह में यह सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। यहां भी रोजाना 40 से 50 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। संचालन की निगरानी के लिए सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा अंडकोषों के निस्तारण के लिए आधुनिक मशीन भी लगाई गई है।

नए बस स्टैंड के पास एबीसी सेंटर बनकर तैयार है।ट्रांसफर होने के बाद संचालन की जिम्मेदारी संस्था को दी जाएगी।निगम की ओर से स्टाफ भी यहां तैनात किया जाएगा और जून में इसे शुरू कर दिया जाएगा।

- विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर निगम आयुक्त

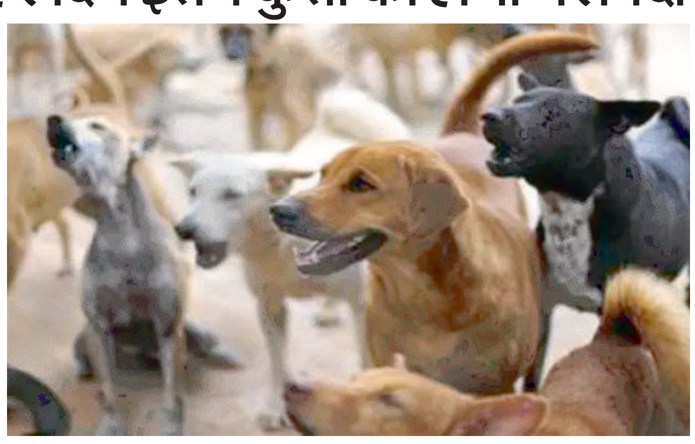

नीति आयोग की 10 वीं वर्किंग काउंसिल ने विज़न विकसित भारत 2047 का ख़ाका खींचा -36 में से 31 राज्यों की ज़बरदस्त अनुकूल उपस्थित- पीएम व विपक्षी मुख्यमंत्रीयों की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ की राजनीति में हम देखते रहते हैं कि पक्ष पक्ष में बहुत कानफ्लिक्ट होते रहता है यानें हर मुद्दे व काम पर आलोचना तर्क वितर्क अड़ंगा होते रहते हैं, जो पक्ष और पक्ष की नीति में वाजिब भी है, मैंने अपने लेखन क्षेत्र में 40 वर्षों की अवधि में बहुत कम बार ऐसा देखा हूं कि पक्ष व विपक्ष मिलकर एक साथ राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए आवाज़ उठाते हैं,परंतु अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका सटीक उदाहरण पूरे पक्ष विपक्ष को मिलाकर 7 एक साथ टीमों में करीब 59 संसद सदस्य, विशेषज्ञ पूरी दुनियाँ में आतंकवाद पर भारत का पक्ष रख रहे हैं जो रेखांकित करने वाली बात है। दूसरी ओर शनिवार दिनांक 24 मई 2025 को मैं देर रात तक संचार माध्यमों मोबाइल टीवी और रेडियो के माध्यम से नीति आयोग की दसवीं गवर्ननिंग काउंसिल मीटिंग पर एकटक सटीक नजरें लगाए रखा था, तथा मीटिंग समाप्त होने के बाद जिस तरह विपक्ष के करीब सभी मुख्यमंत्री की पीएम से आत्मीयता से तथा एक सीएम सर झुकाकर बात कर रहे थे यह देखकर मैं हैरानी से चौका, हालांकि यह सबदेखकर सारी जनता भी चौकी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से यह सब वायरल हो रहा है और पक्ष विपक्ष के साथ साथ होनें तथा विपक्षी मुख्यमंत्रीयों और पीएम की जबरदस्त बॉन्डिंग के समर्थन में जनता के कमेंट्स भी लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनको देखकर मैं सोच रहा था एक समय था, जब चुनाव हो रहे थे तो यही सब आपस में शाब्दिक बणों की तलवारे खींच खींचकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन आज दोस्ती शालीनता व अति मान सम्मान का माहौल दिख रहा था, जिसे पूरी दुनियाँ ने हैरानी व अचंभित होकर रेखांकित किया कि मेरा मानना है या भारतीय संस्कृति का कमाल है, पहले ऑपरेशन सिंदूर व अभी भारतीय मिशन 2047 पर 36 में से 31 राज्यों को उपस्थित रहना, तारीफ-ए-काबिल है, जिसका संदेश पूरे विश्व में पहुंच गया कि भारत के विकास और आतंकवाद पर भारत के पूरे 144.2 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं। यानें हमारे लिए राष्ट्रसुरक्षा आतंकवाद की समाप्ति व राष्ट्र के विकास के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष हम साथ साथ हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए केंद्र व राज्य सरकार को मिलाकर टीम इंडिया बने तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, विज़न 2047 अपनें डेडलाइन के बहुत पहले ही पूरा होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, नीति आयोग की दसवीं वर्किंग काउंसिल ने विजन विकसित भारत 2047 का ख़ाका खींचा -36 में से 31 राज्यों की जबरदस्त अनुकूल उपस्थित-पीएम व विपक्षी मुख्यमंत्रीयों की जबरदस्त बॉन्डिंग देखी।

साथियों बात अगर हम शनिवार दिनांक 24 मई 2025 को दसवीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की करें तो, नीति आयोग की इस बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिरकत की, जो अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी है। लेकिन कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार ने पहले ही अपनी गैरमौजूदगी की सूचना दे दी थी। बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा, यह दिखाता है कि ज्यादातर राज्य सकारात्मक सोच के साथ आए। उन्होंने आगे बताया कि, 'बैठक के एजेंडे में कार्रवाई रिपोर्ट के अलावा दो आइटम शामिल थे। सबसे पहले, बैठक का विषय और एजेंडे में पहला आइटम 'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य' था। पूरा विचार यह है कि पिछली गवर्निंग काउंसिल में, पीएम ने सभी राज्यों से अपने-अपने राज्य के विजन तैयार करने का आह्वान किया था, ताकि उनके पास ऐसे विजन हों जो बाद में एक बड़े समूह में समाहित हो जाएं। राष्ट्र के लिए विजन। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले एक साल से एजेंडा इसी पर आधारित है और यही कारण है कि आज की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय यही रहा'। आगे कहा कि बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पाक में आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने राज्यों से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।पीएम ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए नीतिगत अड़चनों को दूर करने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

साथियों बात अगर हम नीति आयोग की दसवीं वर्किंग की चर्चा को 11 प्वाइंटों में समझने की करें तो, राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10 वीं बैठक ने देश के विकास के लिए एक नया खाका खींचा। पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। (1) नीति आयोग की इस बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिरकत की, जो अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी है। लेकिन कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार ने पहले ही अपनी गैरमौजूदगी की सूचना दे दी थी। सीईओ कहा, 'यह दिखाता है कि ज्यादातर राज्य सकारात्मक सोच के साथ आए।(2)विकसित भारत' का मास्टरप्लानबैठक का मुख्य एजेंडा था, 'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य'। पीएम ने सभी राज्यों से अपने- अपने विकास के विजन को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने का आह्वान किया। यह थीम पिछले साल की बैठक से ही चली आ रही है और अब यह राज्यों के लिए एक रोडमैप बन चुकी है।(3) पीएम ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को एक बार की पहल नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकी ढांचों को नष्ट करने में सटीकता और प्रभावशीलता दिखाई। मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने इसके लिए पीएम के नेतृत्व और सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा की। (4) पीएम ने नागरिक सुरक्षा तैयारियों को संस्थागत और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। हाल ही में हुए मॉक ड्रिल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह नागरिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों को इसे प्राथमिकता देनी होगी।(5) पीएम ने राज्यों को अपनेविकास के लिए लंबी अवधि की योजनाएं बनाने को कहा। हर राज्य अपने संसाधनों, संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। (6) पीएम ने सहकारी संघवाद (कोआपरेटिव फेडरालीस्म) पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे ताकिविकास की गति को और तेज किया जा सके। यह बैठक इस दिशा में एक बड़ा कदम थी।हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। (7) नीति आयोग के सीईओ नेबताया कि बैठक में सकारात्मक माहौल रहा। राज्यों ने अपने अनुभव, चुनौतियां और सफलताएं शेयर कीं, जिससे एक-दूसरे से सीखने का मौका मिला।(8)हालांकि 5 राज्य बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन नीति आयोग ने साफ किया कि इन राज्यों ने पहले ही अपनी गैर मौजूदगी की सूचना दे दी थी। इन राज्यों के साथ अलग से संवाद स्थापित किया जाएगा। (9) बैठक में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन पर भी चर्चा हुई। (10) राज्यों को निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए सुझाव दिए गए।(11) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए नीतिगत अड़चनों को दूर करने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कुल मिलाकर नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे।पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस बैठक में पीएम ने कहा, 'हमारा लक्ष्य प्रत्येक राज्य को विकसित, प्रत्येक शहर को विकसित, प्रत्येक नगर पालिका को विकसित और प्रत्येक गांव को विकसित बनाना होना चाहिए। अगर हम इन तर्ज पर काम करेंगे, तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।' ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पीएम की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ पहली बड़ी बैठक रही जिसमें खासकर विपक्षी मुख्यमंत्री के साथ पीएम की जबरदस्त बॉन्डिंग सभी ने देखी।

अतः अगर हम उपरोक्त पर्यावरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नीति आयोग की 10 वीं वर्किंग काउंसिल ने विज़न विकसित भारत 2047 का ख़ाका खींचा - 36 में से 31 राज्यों की ज़बरदस्त अनुकूल उपस्थित-पीएम व विपक्षी मुख्यमंत्रीयों की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी।केंद्र व राज्यों को मिलकर टीम इंडिया बने तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं-विज़न 2047 अपनें डेडलाइन से बहुत पहले पूर्ण होगा।नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सफ़ल मिटिंग-विपक्षी मुख्यमंत्रीयों व पीएम की जबरदस्त ट्यूनिंग देखकर विश्व हैरान-विज़न 2047 समय पूर्व लक्ष्य हासिल करेगा, मेरा दावा।

कल लॉन्च होगी वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई, कितना दमदार होगा इंजन और कैसे होंगे फीचर्स, जानें कितनी होगी कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

वोक्सवैगन गोल्फ GTI लॉन्च जर्मनी की वाहन निर्माता फॉक्सवैगन की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से प्रीमियम सेगमेंट में Volkswagen Golf GTI को कल औपचारिक तौर पर भारतीय बाजार में लाया जाएगा। इसमें कितना दमदार इंजन मिलेगा। किस तरह के फीचर्स मिलेंगे। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कम कीमत वाली कारों के साथ ही महंगी कारों की भी काफी ज्यादा बिक्री होती है। फॉक्सवैगन की ओर से औपचारिक तौर पर कल Volkswagen Golf GTI कार को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा, कितना दमदार इंजन मिलेगा। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कल लॉन्च होगी Volkswagen Golf GTI

फॉक्सवैगन की ओर से गोल्फ जीटीआई कार को औपचारिक तौर पर कल लॉन्च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इसे प्रीमियम कार सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा।

कैसे होंगे फीचर्स

Volkswagen Golf GTI में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। इसमें 12.9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सात स्पीकर के साथ ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, एंबिएंट लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, की-लैस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, जीटीआई बैजिंग, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, 18 इंच अलॉय व्हील्स, 45 लीटर की क्षमता के पेट्रोल टैंक को दिया जाएगा।

कितनी होगी सुरक्षित

इसमें सात एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, एडेपटिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, फ्रंट असिस्ट, रियर व्यू कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे।

कितना दमदार इंजन

Volkswagen Golf GTI में दो लीटर की क्षमता के टीएसआई इंजन मिलेगा। इस इंजन से कार को 0-100 किलोमीटर की स्पीड हासिल करने में सिर्फ 5.9 सेकेंड का समय लगेगा। दो लीटर के इंजन से कार को 265 हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ ही इसमें 7स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन मिलेगा।

कितनी होगी कीमत

लॉन्च के समय ही इसकी सही कीमत की जानकारी मिल पाएगी। निर्माता इसे सीबीयू के तौर पर भारत लाएगी। ऐसे में संभावित एक्स शोरूम कीमत 50 से 60 लाख रुपये के आस पास हो सकती है।

किनसे है मुकाबला

फॉक्सवैगन की ओर से इस कार को प्रीमियम कार के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला मिनी कूपर जैसी कारों के साथ होगा।

किआ कैरेंस क्लैविस और किआ कैरेंस की कीमत में सिर्फ नौ हजार रुपये का अंतर, जानें किस एमपीवी को खरीदना बेहतर विकल्प

परिवहन विशेष न्यूज

किआ एमपीवी तुलना साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में अब दो विकल्प ऑफर किए जा रहे हैं। जिनमें Kia Carens Clavis और Kia Carens शामिल हैं। इन दोनों में से गाड़ी को खरीदना आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 23 मई 2025 को ही अपनी नई एमपीवी Kia Carens Clavis को लॉन्च किया है। इसके पहले किआ की ओर से सिर्फ कैरेंस की बिक्री की जाती थी। Kia Carens Claivs Vs Kia Carens के बीच किस एमपीवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। आइए जानते हैं।

Kia Carens Clavis Vs Kia Carens इंजन

किआ कैरेंस क्लाविस के बेस वेरिएंट में दो इंजन के विकल्प दिए जा रहे हैं। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है जिसके साथ छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। वहीं दूसरे इंजन के विकल्प के तौर पर 1.5 लीटर की क्षमता का डीजल इंजल मिलेगा। इसके साथ भी छह स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया जाएगा।

वहीं Kia Carens में तीन इंजन के विकल्प दिए जाएंगे। इसमें Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT, Smartstream G1.5 6MT और 1.5L CRDi VGT 6MT वेरिएंट के ही विकल्प मिलेंगे।

Kia Carens Clavis Vs Kia Carens फीचर्स

Kia Carens Clavis के बेस वेरिएंट के तौर पर ऑफर किए जाने वाले HTE में भी कई बेहतरीन फीचर्स (Clavis variant wise features) को ऑफर किया जा रहा है। इसमें 15 और 16 इंच व्हील्स, आइस क्यूब हेलोजन हेडलाइट्स, एलईडी टेल लैंप, पोल टाइप एंटीना, इंडिगो मेटल पेंट डैशबोर्ड, टू टोन इंटीरियर, लगेज बोर्ड, सेमी लेदरेट सीट्स, डबल डी स्टेयरिंग व्हील, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, मैनुअल ड्राइवर सीट हाइड एडजस्ट, मैनुअल एसी, दूसरी और तीसरी रो में एसी वेंट, की-लैस एंट्री, फोलडिंग की, 12.5 इंच एलसीडी क्लस्टर, 4.2 इंच एमआईडी, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

वहीं Kia Carens में 15 और 16 इंच टायर, हेलोजन लैंप, हेलोजन टेल लैंप, शार्क फिन एंटीना, टिल्ट स्टेयरिंग, पावर विंडो, रियर व्यू कैमरा, 12.5 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, सेमी लेदरेट सीट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, की-लैस एंट्री, सात रंगों के विकल्प सहित कई फीचर्स मिलेंगे।

Kia Carens Clavis Vs Kia Carens सेफ्टी फीचर्स

Kia Carens Clavis में छह एयरबैग, एबीएस, बीएएस, ईएससी, वीएसएम, हिल असिस्ट, ईएसएस, डीबीसी, टायर प्रैशर सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, थ्री पाइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक को दिया जा रहा है।

वहीं Kia Carens में एबीएस, ईबीडी, ईएससी, एचएसी, वीएसएम, डीबीसी, छह एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे।

Kia Carens Clavis Vs Kia Carens कीमत

किआ की ओर से कैरेंस क्लाविस की एक्स शोरूम कीमत 11.50 लाख रुपये रखी गई है। यह कीमत इसके बेस वेरिएंट HTE की है।

वहीं किआ की ओर से कैरेंस को सिर्फ एक ही वेरिएंट Premium Optional में ऑफर किया जा रहा है। इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11.41 लाख रुपये है।

सुजुकी ई एक्सेस स्कूटर किस तारीख को हो सकता है लॉन्च, मिलेंगे कैसे फीचर्स और कितनी हो सकती है कीमत, जानें डिटेल

दो पहिया वाहन निर्माता Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर Suzuki E Access को लॉन्च किया जाएगा। सुजुकी की ओर से किस तारीख में ई-एक्सेस स्कूटर को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। किस तरह के फीचर्स और रेंज को दिया जा सकता है। आइए जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जापान की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल सुजुकी की ओर से भारत में कई सेगमेंट में स्कूटर और मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही पहले Electric Scooter Suzuki E Access को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। सुजुकी की ओर से कब तक पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया जा सकता है। इसमें किस तरह के फीचर्स और रेंज को दिया जा सकता है। इसकी संभावित कीमत क्या हो सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जल्द लॉन्च होगा Suzuki E Access इलेक्ट्रिक स्कूटर

सुजुकी की ओर से जानकारी दी गई है कि वह जल्द ही अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर Suzuki E Access को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। निर्माता की ओर से इस स्कूटर को 11 जून 2025 को औपचारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

कैसे होंगे फीचर्स

सुजुकी की ओर से अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Suzuki E Access में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। इसमें सुजुकी राइड कनेक्ट एप, कलर्ड टीएफटी एलसीडी स्कीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट, की-फॉब, मल्टी फंक्शन स्टार्टर स्विच, ड्राइविंग के लिए ईको, राइड ए, राइड बी और रिवर्स मोड सहित कई फीचर्स को दिया गया है।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर

Suzuki E Access इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.07 KWh की क्षमता की लिथियम ऑयन फास्फेट बैटरी को दिया है। इस बैटरी को पोर्टेबल चार्जर से 6.42 घंटे में और फास्ट चार्जर से 2.12 घंटे में 0-100 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 71 किलोमीटर प्रति घंटे तक है और इसमें लगी बैटरी से इसे 4.1 किलोवाट की पावर और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। फुल चार्ज होने के बाद इसे 95 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

कितनी होगी कीमत

लॉन्च के समय ही स्कूटर की सही कीमत की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस स्कूटर को सुजुकी की ओर से एक लाख रुपये से 1.10 लाख रुपये की संभावित एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

किनसे होगा मुकाबला

सुजुकी की ओर से जब इस स्कूटर को औपचारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। तब इसका सीधा मुकाबला Honda Activa Electric और Honda QC1 के अलावा Ather, Ola, Vida जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ होगा।

टाटा हैरियर के डार्क एडिशन को है घर लाना, पांच लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद जाएगी कितनी ईएमआई, पढ़ें खबर

परिवहन विशेष न्यूज

कार फाइनेंस योजना टाटा मोटर्स की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Tata Harrier को ऑफर किया जाता है। इसके Dark Edtion को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ पांच लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर Tata Harrier को घर लेकर आया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता मिड साइज एसयूवी के तौर पर Tata Harrier को ऑफर करती है। इसके Dark Edition को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं, तो सिर्फ पांच लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर मिड साइज सेगमेंट की एसयूवी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

Tata Harrier Price

Tata Motors की ओर से SUV सेगमेंट में Tata Harrier को ऑफर किया जाता है। इसके Dark Edition को 19.15 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसे दिल्ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 22.13 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 19.15 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के अलावा करीब 1.94 लाख रुपये आरटीओ और इंश्योरेंस के करीब 7285 हजार रुपये देने होंगे। टीसीएस चार्ज के तौर पर 19 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।

पांच लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर इस गाड़ी के Dark Edition को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में पांच लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 17.13 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 17.13 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 27571 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 17.13 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 27571 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Harrier के Dark Edition के लिए करीब छह लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 28.15 लाख रुपये देंगे।

किनसे होगा मुकाबला

Tata Motors ओर से Harier को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इसका सीधा मुकाबला Tata Safari के अलावा Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara, Mahindra Scorpio, Kia Seltos, Honda Elevate जैसी मिड साइज एसयूवी के साथ होता है।

टाटा कर्व vs हुंडई क्रेटा प्राइस, फीचर्स और इंजन में कितना अंतर, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को देश में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। चार मीटर से ज्यादा बड़ी एसयूवी में टाटा की ओर से कर्व को ऑफर किया जाता है। वहीं इस सेगमेंट में हुंडई की ओर से क्रेटा को बिक्री के लिए ऑफर किया जाता है। फीचर्स कीमत और पावर के मामले में किस एसयूवी को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में किसी भी अन्य सेगमेंट के मुकाबले में एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली कारों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में टाटा की ओर से कर्व की बिक्री की जाती है, तो हुंडई की ओर से भी क्रेटा को ऑफर किया जाता है। फीचर्स, कीमत और पावर के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना (Tata Curvv vs Hyundai Creta) आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Curvv vs Hyundai Creta इंजन

टाटा कर्व के पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्पीड मैनुअल और 7डीसीए ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जाता है।

वहीं Hyundai Creta में इंजन के तीन विकल्प मिलते हैं। जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन से 115 पीएस पावर और 143.8 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर 1.5 लीटर टर्बो इंजन मिलता है जिससे 160 पीएस की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तीसरे विकल्प के तौर पर 1.5 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन मिलता है। जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इन विकल्पों के साथ 6स्पीड मैनुअल, आईवीटी, ऑटोमैटिक और 7स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं।

Tata Curvv Vs Hyundai Creta फीचर्स

Tata Curvv में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें शॉर्क फिन एंटीना के साथ जीपीएस, ड्यूल टोन रूफ, ऑटो हैडलैंप, इंटीग्रेटिड रियर स्पॉयलर, एलईडी डीआरएल, सीक्वेंशनल टर्न इंडीकेटर्स, वॉयस असिस्ट पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टिड टेल लैंप, 18 इंच अलॉय व्हील्स, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मूड लाइटिंग, फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, जेस्टर पावर्ड टेलगेट, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट वेंटिलेडिट सीट्स, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हरमन ऑडियो सिस्टम, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं Hyundai Creta में 17 इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, सीक्वेंशल टर्न इंडीकेटर, शॉर्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन एक्सटीरियर और इंटीरियर, लेदर सीट्स, रियर विंडो सनशेड, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन ऑटो एसी, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस फोन चार्जर, ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड्स, स्नो, मड और सैंड ट्रैक्शन मोड्स, क्रूज कंट्रोल, की-लैस एंट्री, फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज, रिमोट इंजन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, रियर एसी वेंट्स, रियर वाइपर और वॉशर, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, आईएसजी, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बोस के आठ स्पीकर ऑडियो सिस्टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूलिंक तकनीक, ओटीए अपडेट्स, होम टू कार के साथ एलेक्सा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Tata Curvv Vs Hyundai Creta सेफ्टी फीचर्स

Tata की ओर से Curvv एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग को दिया गया है। जबकि सेफ्टी के लिए आई-टीपीएमएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, थ्री पाइंट सीटबेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 360 डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, इमोबिलाइजर, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डीसेंट कंट्रोल, ईपीबी, एबीएस, ईबीडी, Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

वहीं Hyundai Creta में 6 एयरबैग, ईबीडी, ईएससी, वीएसएम, हिल स्टार्ट कंट्रोल, टीपीएमएस, रियर डिस्क ब्रेक, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर्स, थ्री पाइंट सीटबेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, ईएसएस, ऑटो हेडलैंप, हेडलैंप एस्कॉर्ट, पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, Level-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Tata Curvv Vs Hyundai Creta कीमत

Tata Curvv ICE की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 19.48 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है।

वहीं कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में क्रेटा की कीमत 11.10 लाख रुपये एक्स शोरूम से 20.49 लाख रुपये एक्स शोरूम तक है।

अधिकांश युवाओं के पास नौकरियां क्यों नहीं हैं ?

पी. चिदम्बरम

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र पर हाल ही में दो रिपोर्ट आई हैं, एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.बी.डी.आई.) की और दूसरी नीति आयोग की। दोनों ही आधिकारिक रिपोर्ट हैं। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वाॢषक...

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र पर हाल ही में दो रिपोर्ट आई हैं, एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.बी.डी.आई.) की और दूसरी नीति आयोग की। दोनों ही आधिकारिक रिपोर्ट हैं। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वाॢषक सर्वेक्षण(ए.एस.यू.एस.ई.) भी है।

बुनियादी तथ्य, विशेषताएं : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के बारे में कौन से बुनियादी तथ्य इन दोनों रिपोर्टों से प्राप्त किए जा सकते हैं?

वर्तमान वर्गीकरण के तहत, सूक्ष्म उद्यमों में निवेश सीमा 2.5 करोड़ रुपए तक और कारोबार सीमा 10 करोड़ रुपए तक है; लघु उद्यमों में 25 करोड़ रुपए तक और 100 करोड़ रुपए तक है; और मध्यम उद्यमों में 125 करोड़ रुपए तक और 500 करोड़ रुपए तक है। इस वर्गीकरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में कुछ हजार उद्यमों को छोड़कर बाकी सभी उद्यम एम.एस.एम.ई. हैं।

एम.एस.एम.ई. की कुल संख्या का वितरण माइक्रो के पक्ष में है। हिस्सेदारी माइक्रो-98.64 प्रतिशत; लघु-1.24 प्रतिशत; और मध्यम-केवल 0.12 प्रतिशत है।

स्वामित्व में प्रोपराइटरशिप (59 प्रतिशत), भागीदारी (16प्रतिशत), एल.एल.पी. (1 प्रतिशत), प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (23प्रतिशत) और पब्लिक लिमिटेड कंपनी (1 प्रतिशत) शामिल हैं।

भारत में लगभग 7,34,00,000 एम.एस.एम.ई. हैं। इनमें से लगभग 6,20,00,000 मार्च 2025 तक उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में लगभग 24 प्रतिशत (लगभग 30 लाख करोड़ रुपए) का ऋण अंतर है; सेवा उप-क्षेत्र में यह अंतर 27 प्रतिशत है और महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में यह 35 प्रतिशत है।

एम.एस.एम.ई. ने 2023-24 में भारत के व्यापारिक निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दिया। कुल मिलाकर, 2024-25 में निर्यात करने वाले एम.एस.एम.ई. की संख्या 1,73,350 थी (जो एम.एस.एम.ई. की कुल संख्या का 1 प्रतिशत का अंश है)। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख सामान में रेडीमेड गार्मैंट, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और ऑटो कंपोनैंट हैं। एक को छोड़कर सभी कम तकनीक वाले सामान हैं।

एम.एस.एम.ई. के लिए ऋण सहायता योजनाओं और विकास योजनाओं की भरमार है। रिपोर्ट पढ़ते हुए, मैंने कम से कम 2 सबसिडी योजनाओं, 4 क्रैडिट गारंटी योजनाओं और कम से कम 13 विकास योजनाओं की गिनती की। 2025-26 के बजट में पहली बार उद्यमियों के लिए एक योजना और एक क्रैडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई। इसने एक नए फंड ऑफ फंड्स, एक डीप टेक फंड ऑफ फंड्स और एक नए स्ट्रीट वेंडर्स निधि (पी.एम. स्वनिधि) की भी घोषणा की।

एम.एस.एम.ई.रोजगार सृजन का प्राथमिक स्रोत है। यह दावा किया जाता है कि इस क्षेत्र द्वारा सृजित कुल रोजगार लगभग 26 करोड़ है। नौकरियां हैं, व्यक्ति नहीं: अब, आइए इस निबंध के मुख्य प्रश्न पर आते हैं। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों में, रिपोर्ट सूचीबद्ध करती है - कुशल श्रमिकों की कमी, कौशल अंतराल और प्रतिभा को आकर्षित करने में कठिनाई। ये निष्कर्ष देश में बेरोजगारी की पूरी कहानी बताते हैं। यह मानना उचित है कि बड़े उद्योग (जिनमें 125 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार है) उच्च शैक्षणिक योग्यता और उच्च कौशल वाले व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, जो कि अधिकांश बेरोजगारों के पास नहीं है। दूसरी ओर, एम.एस.एम.ई. को श्रमिकों की आवश्यकता है; फिर भी, यदि उनके पास श्रमिकों

की कमी है और प्रतिभा को आकृषत करने में कठिनाई है, तो क्यों? खेदजनक लेकिन अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि, सबसे पहले, नौकरियों के लिए आवेदकों के पास नौकरियों को भरने के लिए शिक्षा या कौशल नहीं है और, दूसरी बात, उद्यम की संरचना या पारिश्रमिक के कारण प्रस्तावित नौकरियां आकर्षक नहीं हैं।

संरचनात्मक तथ्यों और रोजगार परिणामों का मिलान करके, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि भारत के युवाओं में उच्च बेरोजगारी क्यों है।

*अप्रैल 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ थी।

*श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो या तो काम कर रहा है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है। यह 55.6 प्रतिशत या लगभग 81 करोड़ है।

*श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.) कुल जनसंख्या में कार्यरत लोगों के अनुपात को परिभाषित करता है। यह 52.8 प्रतिशत या लगभग 77 करोड़ है।

*बेरोजगार व्यक्तियों की पूर्ण संख्या अंतर है, अर्थात, 4 करोड़। यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन याद रखें, यह 'सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश' करने वालों की संख्या से बाहर है। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से रोजगार की तलाश छोड़ दी है।

*आधिकारिक बेरोजगारी दर 4 करोड़/81 करोड़ है जो 5.0 प्रतिशत के बराबर है।

समाधान का मार्ग:एम.एस.एम.ई. की सबसे बड़ी संख्या 'सूक्ष्म' है जो 98.64 प्रतिशत है। इस तथ्य के साथ कि स्वामित्व और भागीदारी सभी एम.एस.एम.ई.का 75 प्रतिशत हिस्सा है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि 26 करोड़ 'रोजगार' में से अधिकांश परिवार के सदस्य और रिश्तेदार हैं जो परिवार द्वारा संचालित उद्यमों में काम करते हैं। यह 'लघु' और 'मध्यम' (एम.एस.एम.ई.का 1.36 प्रतिशत या लगभग 10,00,000) हैं जो वास्तव में लोगों को रोजगार देते हैं जहां मालिक और नौकर का रिश्ता होता है।

नौकरियों का 'आपूर्ति' पक्ष 10,00,000 एम.एस.एम.ई. से आना चाहिए। नौकरियों के लिए 'मांग' पक्ष उन युवा पुरुषों और महिलाओं से आना चाहिए जो स्कूल छोड़ चुके हैं या जिनके पास स्कूली शिक्षा है या जिनके पास बुनियादी कला या विज्ञान की डिग्री है।

संभावित नियोक्ता ऋण की कमी, दमनकारी विनियमन और कई योजनाओं और अनुपालनों से प्रभावित होते हैं। संभावित कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, कौशल की कमी और प्रशिक्षण की अनुपस्थिति से बाधा होती है। संक्षेप में, बहुत कम 'प्रतिभा' है।

शासन को इन कमियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला पड़ाव कौशल प्रशिक्षण के साथ स्कूली शिक्षा है। अगला पड़ाव एस.एम.ई. (ध्यान दें कि मैंने एम को हटा दिया है) को केवल एक उदार ऋण-सह-ब्याज सबसिडी योजना के साथ मदद करना है। इसे सरल रखें।-पी. चिदम्बरम

चिठिया हो तो ......

विजय गर्ग

कागज पर कलम से लिखी चिट्ठियां महज चिट्ठियां नहीं होतीं, ये अपने समय का दस्तावेज होती हैं, जिसमें अनुराग, पीड़ा, आत्मीयता, स्मृति, उम्मीद, बिछोह का दुख, मिलन की आस, समकालीन लोक संस्कृति सब कुछ होता है। एक-एक शब्द में हजारों भावों की गठरी बंधी हुई होती है। पुराने समय में दूर देशों में रह रहे हमारे आत्मीयजनों की चिट्ठियां जब आती थीं, तो उन्हें पढ़ते हुए लगता था जैसे वे सामने बैठ कर हमसे अपनी बात कह रहे हैं, बस दिखाई नहीं दे रहे हैं । इसीलिए नई नवेली दुल्हनें परदेस गए पिया की और प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों की चिट्ठियां बार-बार पढ़ती थीं। वह भी सबसे छिप कर कि कहीं चिट्ठियों में अंकित उनके इस छिप कर मिलने के उछाह को कोई देख न ले। पहले की पीढ़ी को पता होगा कि किसी की चिट्ठी के इंतजार में कितनी खुमारी, कितना रोमांच और कितनी तड़प होती है । और जब चिट्ठी हाथ में हो, तो हर्ष के अतिरेक से देह हल्की होकर हवा तैरने लगती है। ये होता है पत्र लिखने का जादू और पाने का आनंद। बड़े दुख की बात है कि मोबाइल युग में पैदा हुई पीढ़ियां इस जादुई आनंद को कभी महसूस ही नहीं कर पाईं।

सच कहा जाए तो पत्र लिखना एक कला है । जब हम अपने दिल की बात को कागज पर लिखते तो वह बात पढ़ने वाले की स्मृति में कहीं गहरे तक अंकित हो जाती है। वह हमारे 'चैट बाक्स' में लिखी बातों से कहीं ज्यादा स्थायी और प्रभावी होती है। हाथ से पत्र लिखने का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। मसलन, लिखते वक्त हमारा दिमाग एकाग्र होता है। जिस तरह हम कागज-कलम उठा कर व्यवस्थित तरीके से लिखने बैठते हैं, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी लिखी जा रही उस बात को अपने अंदर व्यवस्थित कर रहा होता है। एक तरह से यह हमारे दिमाग की कसरत भी हुई। नई तकनीक लोगों को लिखने से वंचित कर रही । लिखने से छुट्टी पाकर या लेकर हम खुश भी हो रहे । इस छुट्टी के कुछ फायदे गिनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है यह छुट्टी हमारी भावनाओं से भी हमें दूर कर रही है। हम सोच सकते हैं कि भला जो भाव हम अपने हाथों से लिख कर पत्र पर उकेर सकते हैं, क्या वह वाट्सऐप संदेश में भर सकते हैं । कतई नहीं। डिजिटल संदेश जितनी जल्दी लिखे जाते हैं, उतनी ही जल्दी उनका प्रभाव भी मिट जाता है।

हाथ से लिखे पत्रों की अहमियत की बात करें, तो महान लोगों के पत्र आज भी देश की धरोहर माने जाते हैं। उनका बाकायदा अध्ययन मनन होता है। कोई बड़ा व्यक्ति किसी आम आदमी को हाथ से पत्र लिख कर भेजे, तो वह पत्र उसकी अनमोल संपदा का हिस्सा बन जाता है । वह उसे जीवन भर संभाल कर रखता है। मशीनी शब्दों में जीवित भावनाओं का अभाव - सा रहता है। अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने जो चिट्ठियां लिखीं, वह न सिर्फ एक कालखंड का इतिहास थीं, बल्कि भविष्य की अमानत भी बन गईं। मगर आज डिजिटल युग में सब कुछ टंकित हो गया है । हमें पत्र के नीचे बने सिर्फ हस्ताक्षर को देख कर संतोष करना पड़ता है,

नब्बे के दशक में टीवी रेडियो पर अनेक कार्यक्रम ऐसे थे, जिनमें दर्शकों और श्रोताओं से चिट्ठियां मंगवाई जाती थीं । सुरभि कार्यक्रम में प्रस्तोता के पीछे लगे चिट्ठियों के ढेर को भला कौन भूल सकता है । रेडियो पर फरमाइशी गानों के लिए जब चिट्ठियां लिखी जाती थीं, तो उनमें कार्यक्रम और प्रस्तोताओं के लिए अपने लगाव का भी इजहार किया जाता था । कितनी प्यारी और मीठी बातें लिखी होती थी। जिन्हें पढ़ते हुए कई बार महिला रेडियो सखी भी खुश हुए बिना नहीं रह पाती थीं । कुछ समय पहले डायरी विधा में लिखी हुई किताब पढ़ रही थी- 'बंजारे की चिट्टियां' । डायरी भी एक तरह का पत्र ही है। अपने ही नाम लिखे पत्र । लेखक ने रेत के हर कण को, रोशनी को, सांझ के अंधियारे को, सूरज को, चंदा को, वक्त को, दर्द को, दोस्त को, दुश्मन को और उसकी निगाह में आने वाली हर शय को इन चिट्टियों में उतार दिया था । ऐसे, जैसे सब जीवित होकर पढ़ने वाले के साथ चल रहे हों। ऐसे, जैसे राजस्थान में चलने वाली आंधियां हमारे चेहरे से टकरा रही हों। ऐसे, जैसे समय हमको छू रहा हो । जैसे समय को हम महसूस कर रहे हों। ये होती है चिट्टियों की ताकत । चिट्टियों में लिखे भावों की ताकत को और समझना है तो 'नाम' फिल्म की उस गजल को सुनना चाहिए- चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। इस गजल को गाते हुए कई बार पंकज उधास रो देते थे ।

आज जब हर ओर डिजिटल माध्यमों का शोर है, वीडियो और रील में दिखावे की धक्का-मुक्की है, डिजिटल की जमीन पर संवेदनाओं का अकाल और धोखाधड़ी की बाढ़ है, फटाफट आए वाट्सऐप चैटबाक्स, ईमेल के डिजिटल संदेशों को पढ़ते-पढ़ते दुनिया उकता और थक गई है, तब भावों से भरे, कामनाओं से सजे, लगावों से लिखे और संभावनाओं से संवरे एक अदद पत्र की अहमियत और भी बढ़ गई है। काश कि कलम से कागज पर चिट्ठियां लिखने का चलन फिर से लौट आए।

बहुभाषी शिक्षा को मिले बढ़ावा

विजय गर्ग

केंद्र सरकार ने देश की भाषायी विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत गर्मी की छुट्टियों में देशभर के सभी 14.5 लाख स्कूलों में 'भारतीय भाषा समर कैंप 2025' का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में बच्चों को खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी मातृभाषा के साथ-साथ एक या अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। यह समर कैंप एक सप्ताह का होगा, जिसमें बच्चों को भारतीय भाषाओं से जोड़ने के लिए प्रतिदिन चार घंटे की गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिससे कुल 48 घंटे का प्रशिक्षण होगा। कैंप के अंत में बच्चों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस 'भारतीय भाषा समर कैंप का लाभ 25 करोड़ से अधिक बच्चे उठा सकेंगे।

आज के समय में रोजगार या बेहतर जीवन यापन के लिए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। बैंक कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों और आइटी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को अक्सर महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, तमिलनाडु या अन्य राज्यों में नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें स्थानीय भाषा और संस्कृति की भिन्नता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संवाद की कमी के कारण विवाद भी उत्पन्न होते हैं। हाल में कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें स्थानीय भाषा मराठी और कन्नड़ में बात करने पर जोर दिया गया है। मातृभाषा का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। भारत एक विविधता से भरा देश है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं मिलती हैं। सभी भाषाओं का समान महत्व है, और लोगों को एक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए। इससे उन्हें किसी अन्य राज्य में जाने पर भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा । बहुभाषी लोग विभिन्न संस्कृतियों के साथ संवाद कर सकते हैं। और एक-दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक शोध के अनुसार, एक से अधिक भाषाएं सीखने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। बहुभाषी शिक्षा विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे भारत में सामाजिक एकता और सद्भाव को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारत की भाषायी विविधता और विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बहुभाषी शिक्षा के लाभ से अनजान हैं। अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं को भी महत्व देना चाहिए। हालांकि बहुभाषी शिक्षा को केवल स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

आज के बच्चे अंकों में तो अव्वल हैं पर जीवन की परीक्षा में अक्सर असफल ?

यह वाक्य सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन हमारे समय की कड़वी सच्चाई को पूरी तरह उजागर करता है। भारत के शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड हर वर्ष शानदार परीक्षा परिणामों की घोषणा करते हैं। बच्चों के अंक 100 प्रतिशत आने लगे हैं। शहर, जिला और राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों की तस्वीरें अखबारों और सोशल मीडिया पर छपती हैं। स्कूल और कोचिंग सेंटर बड़े-बड़े बैनर लगाकर दावा करते हैं- हमारे यहां से टॉपर निकले हैं।

बाहरी दुनिया को देखकर लगता है। - देश में एक होनहार पीढ़ी तैयार हो रही है। लेकिन जब हम शिक्षा की आंतरिक परतों को टटोलते हैं, तो मन में यह सवाल गूंजने लगता है x क्या हम बच्चों को इंसान बना रहे हैं या सिर्फ अंक लाने की मशीन ?

अंक किसके ? श्रेय किसे ?

एक ओर कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर बच्चों की सफलता का श्रेय लेते हैं। वे कहते हैं, हमारी गाइडेंस से टॉपर बना। दूसरी ओर स्कूल प्राचार्य और प्रबंधन कहते हैं, हमारे शिक्षक और पाठ्यक्रम की बदौलत यह परिणाम आया। लेकिन जब उन्हीं बच्चों से बात करें, तो वे कहते हैं, मैंने किसी ट्यूशन की मदद नहीं ली, ये मेरी मेहनत है। यह विरोधाभास कुछ और नहीं, बल्कि एक दिखावटी व्यवस्था की उपज है, जिसमें सच को छुपाना ही सामान्य हो गया है।

शिक्षा का मकसद- समझ या नंबर ?

हमारे यहां परीक्षा का मतलब अब रट्टा मारो और अंक लाओ बन चुका है। सोचने समझने की जगह शॉर्टकट्स और गाइड्स ने ले ली है। एक बच्चा जो 99 प्रतिशत लाता है, वह जरूरी नहीं कि जीवन की समस्याओं से जूझने का हुनर भी जानता हो।

उदाहरणः एक बार दिल्ली की एक छात्रा ने 96 प्रतिशत अंक लाने के बाद आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे लगा वह अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। बिहार में एक छात्र को जब 100 में 100 अंक मिले, तो टीवी पर पूछे गए सामान्य ज्ञान के सवाल का जवाब तक नहीं आया। यह आंकड़े हमें चौंकाते हैं कि शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं।

टॉपर संस्कृति बनाम इंसानी मूल्य

बच्चे अब दूसरों को हराने के लिए पढ़ते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए नहीं। टॉपर बनने की होड़ में मित्रता, सहृदयता, खेल, संगीत, आत्मचिंतन - सब कुछ पीछे छूट गया है। माता-पिता बच्चों की तुलना पड़ोसी के बेटे-बेटी से करते हैं- देखो वो 98 प्रतिशत लाया है, तुम क्यों नहीं ? इस तुलना ने बच्चों की आत्मा से सीखने की सहजता को छीन लिया है।

और क्या खो रहे हैं हम ?

मानसिक स्वास्थ्यः डिप्रेशन, एंग्जायटी, आत्महत्या की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ रही हैं। जीवन कौशलः 12वीं में 99त्र लाने वाला छात्र, कॉलेज में आत्मनिर्भर होना नहीं सीख पाता।

आत्मविश्वासः एक परीक्षा में कम अंक आने पर बच्चा खुद को असफल मान लेता है।

समाधान क्या है ?

अंकों से अधिक कौशल पर ध्यानः कक्षा में बच्चों की रचनात्मकता, तर्कशक्ति, नेतृत्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को स्थान मिले।

मूल्य आधारित शिक्षाः ईमानदारी, सहयोग, सहिष्णुता, और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

कोचिंग कल्चर पर पुनर्विचारः स्कूलों को इतना सक्षम बनाना होगा कि बच्चों को अलग से ट्यूशन की आवश्यकता ही न हो। माता-पिता की भूमिकाः अपेक्षाओं से अधिक समझ, प्यार और संवाद जरूरी है।

अंत में एक सवालः क्या हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां 99 प्रतिशत अंक लाने वाला बच्चा भी खुद से पूछे क्या मैं खुश हूं? अगर उत्तर नहीं है, तो हमें अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। हमें इंसान बनाना है, न कि सिर्फ टॉपर ।

-विजय गर्ग

तेजस्वी प्रसाद यादव ही 'असल बिहारी'

इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। पटना में आर.जे.डी. नेता और पूर्व सी.एम. राबड़ी देवी के आवास के पास एक पोस्टर ने पूर्व डिप्टी सी.एम. तेजस्वी प्रसाद यादव को 'असली (शुद्ध देसी) बिहारी' घोषित...

इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। पटना में आर.जे.डी. नेता और पूर्व सी.एम. राबड़ी देवी के आवास के पास एक पोस्टर ने पूर्व डिप्टी सी.एम. तेजस्वी प्रसाद यादव को 'असली (शुद्ध देसी) बिहारी' घोषित करके विवाद खड़ा कर दिया है, जबकि एल.जे.पी.(आर.वी.) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बाहरी करार दिया है।

एक महिला आर.जे.डी. पदाधिकारी द्वारा लगाए गए पोस्टर में सी.एम. नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सम्राट चौधरी का भी मजाक उड़ाया गया है, जिसमें उन्हें चिराग के सिर पर मुकुट रखते हुए दिखाया गया है।

कैप्शन में लिखा था : 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने'। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें आर.सी.पी. सिंह के नाम से जाना जाता है, ने अपने पुराने आलोचक प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया। सिंह ने अपनी आप सबकी आवाज पार्टी का विलय किशोर की जन सुराज पार्टी में कर दिया।

छगन भुजबल एक बार फिर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में वापसी कर रहे : महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है क्योंकि वरिष्ठ एन.सी.पी. और ओ.बी.सी. नेता छगन भुजबल एक बार फिर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में वापसी कर रहे हैं। महायुति सरकार स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य भर में अपने ओ.बी.सी. वोट बैंक को मजबूत करने के लिए धनंजय मुंडे की जगह एक मजबूत ओ.बी.सी. चेहरे के रूप में उन्हें लाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार, एन.सी.पी. के शीर्ष नेतृत्व की कुछ अनिच्छा के बावजूद, फडऩवीस भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के लिए उत्सुक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता, भुजबल ओ.बी.सी. माली समुदाय से आते हैं और लंबे समय से ओ.बी.सी. अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रभावशाली वकील रहे हैं। 77 वर्षीय भुजबल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली महायुति कैबिनेट में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे।

पिछले साल के अंत में जब फडऩवीस सरकार ने कार्यभार संभाला था, तो एन.सी.पी. अध्यक्ष और उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार कथित तौर पर अपने सहयोगी धनंजय मुंडे को बढ़ावा देने के इच्छुक थे। भुजबल को दरकिनार कर दिया गया और मुंडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति का प्रभार दिया गया। भुजबल को शामिल करने का मतलब है कि एन.सी.पी. ने गठबंधन में अपने मंत्रियों का कोटा बरकरार रखा है, साथ ही उस नेता को खुश किया है जो महायुति सरकार में पद से वंचित होने से नाराज थे।

वाम दलों की बड़ी रणनीति में भाजपा के चुनावी विस्तार को रोकना चुनौती है: सी.पी.आई. (एम) और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, अगले साल केरल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के सपने को साकार करने की उम्मीद कर रहे हैं। सी.पी.आई. (एम) के नेतृत्व वाला एल.डी.एफ. विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यू.डी.एफ. के साथ उच्च दाव की लड़ाई के लिए कमर कस रहा है। हालांकि, विजयन अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों पर जोर देते हुए राज्य के सभी 14 जिलों का दौरा कर रहे हैं। एल.डी.एफ. ने सत्ता विरोधी भावना को मात देते हुए 140 सदस्यीय विधानसभा में 99 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। 4 दशकों में यह पहली बार था जब राज्य ने सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए लगातार 2 कार्यकालों के लिए मतदान किया था। इस बीच, सी.पी.आई. (एम) ने विकास के मुद्दे को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है और विजयन को ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जिसने कई विकास परियोजनाएं पूरी की हैं। हालांकि, वाम दलों की बड़ी रणनीति में भाजपा के चुनावी विस्तार को रोकना चुनौती है।

शरद पवार और अजीत पवार गुट रस्साकशी में लगे : महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और अजीत पवार गुटों के विलय की संभावना पर अटकलों के बीच, दोनों पक्ष कहानी को नियंत्रित करने के लिए रस्साकशी में लगे हुए हैं। इस बीच, शरद पवार के गुट में संकट बढ़ रहा है क्योंकि कथित तौर पर कुछ विधायकों ने अजीत पवार की पार्टी के साथ विलय का समर्थन किया है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि विलय की अफवाह पवार सीनियर द्वारा अपने गुट से पलायन को रोकने के लिए फैलाई जा रही है। 288 सदस्यीय विधानसभा में शरद पवार के गुट के सिर्फ 10 विधायक हैं जबकि इसने 2024 में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 8 पर जीत हासिल की है। विलय पर शरद पवार की टिप्पणी को पीछे हटने के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, शरद पवार ने कहा था कि इसका फैसला उनकी बेटी और उनके गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और अजीत पवार करेंगे। सुप्रिया सुले ने विलय की दिशा में किसी भी कदम को खारिज कर दिया लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार को विलय की जरूरत है।

मायावती का चुपचाप यू टर्नः एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बहुजन समाज पार्र्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। संगठनात्मक बदलाव के तहत मायावती ने देश को तीन जोन में बांटकर टीमों के गठन का निर्देश दिया है जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक राष्ट्रीय समन्वयक करेगा।-राहिल नोरा चोपड़ा

'लाल ताबूत' में आधी कील

नक्सलवाद अर्थात 'लाल आतंकवाद' के ताबूत में लगभग आधी कील घुसेड़ दी गई है। 'लाल आतंकवाद' की सांसें तभी उखड़ गईं, जब सुरक्षा बलों ने सीपीआई (माओवादी) के महासचिव, नक्सलियों की रीढ़ और ऑपरेशनल सरगना गगन्ना उर्फ बासव राजू उर्फ नंबाल्ला केशव राव उर्फ दारापू नरसिम्हा रेड्डी को ढेर कर दिया। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलवाद के खिलाफ करीब तीन दशकों की लड़ाई में बासव महासचिव स्तर का पहला नक्सली था। यह सुरक्षा बलों की शानदार, साहसिक, रणनीतिक सफलता और उपलब्धि है। गगन्ना अप्रैल, 2010 के उस दंतेवाड़ा हमले का 'मास्टरमाइंड' था, जिसमें नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 75 जवानों को 'शहीद' कर दिया था। छत्तीसगढ़ की ही झिरम घाटी में 2013 में राज्य कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के नरसंहार की रणनीति भी बासव ने ही तैयार की थी। बेशक वह खूंखार नक्सली था। वह नक्सलियों के मिलिट्री कमीशन का संचालन करता था, लिहाजा बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बूबी ट्रैप और आईईडी भी गगन्ना ने ही तैयार किए थे। वह आंध्रप्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रशिक्षित बीटेक था, लिहाजा उसने नक्सलियों के हमलों को भी तकनीकी आयाम दिए। बहरहाल 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' का उपसंहार, अंततः, सफल रहा, क्योंकि नक्सलियों का महासचिव मार दिया गया, एक ही दिन में 27 नक्सली भी ढेर किए गए, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 अन्य नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सितंबर, 2023 से 20 मई, 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ में ही 401 नक्सली मारे गए, जबकि 1355 ने आत्मसमर्पण किया। अब नक्सलवाद की मौजूदगी और सक्रियता देश के 7 राज्यों के 18 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। यह मौजूदगी 9 राज्यों के 38 जिलों में होती थी।

लिहाजा हम कह रहे हैं कि 'लाल आतंकवाद' के ताबूत में लगभग आधी कील गाड़ दी गई है। संपूर्ण खात्मा अभी कुछ शेष है, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद का अस्तित्व खत्म करने के जिस लक्ष्य को दोहराते रहते हैं, वह संभव लगता है। दरअसल यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के उस घने जंगल-अबूझमाड़-में सफलता के साथ किया गया है, जहां दशकों तक सरकारी अधिकारी नहीं गए अथवा जाने का साहस नहीं कर पाए और विकास की योजनाएं तो महज एक सपना थीं। नक्सलवादी स्कूलों और पक्की सडक़ों के भी खिलाफ रहे हैं और देश की संसदीय व्यवस्था के भी घोर विरोधी रहे हैं। चारु मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी शहर से जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था, वह लगातार पीछे छूटता गया। किसानों और भूमिहीनों में समान जमीन का वितरण, बंटवारा नहीं हो सका, लेकिन यह आंदोलन पहले वामपंथी उग्रवाद बना और फिर खास किस्म के आतंकवाद में तबदील होता गया। पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का मानना था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक चुनौती रहा है। यह कश्मीर से भी बड़ी और भयावह चुनौती है। ऐसा ही मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह का मानना है, लिहाजा नक्सलवाद का समूल नाश करने की रणनीति पर विचार किया गया। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दौरान नक्सलवाद देश के करीब 160 जिलों में मौजूद और सक्रिय था। तत्कालीन योजना आयोग की एक रपट में उल्लेख किया गया था कि नक्सलियों की सालाना आमदनी 1200 करोड़ रुपए के करीब थी।

अंक जीवन नहीं हैं, बच्चों को दें संबल, बनें मददगार !

देश में सीबीएसई और विभिन्न राज्यों की अन्य बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट(परिणाम) लगभग-लगभग मई माह में घोषित हो चुके हैं। जिन बच्चों ने इन बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए हैं, वे बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ही खुश हैं। लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश बोर्ड(दसवीं और बारहवीं) की परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाए हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो गये हैं, उन बच्चों व बच्चों के अभिभावकों के चेहरों पर चिन्ता की अनेक लकीरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे नाखुश व निराश नजर आ रहे हैं। परीक्षा परिणाम आने पर अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाने पर बच्चों के साथ ही अभिभावकों का नाखुश होना स्वाभाविक, लाज़िमी है, लेकिन जो बच्चे बोर्ड में अपनी अच्छी परफोर्मेंस नहीं दे पाए हैं, उनको हाल फिलहाल माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ की बहुत जरूरत है। इस समय उन्हें(बच्चों को) मानसिक सपोर्ट देने की जरूरत है। अभिभावकों को अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि बोर्ड की परीक्षाएं या कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती है। उन्हें अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा होतीं हैं और असफलताएं ही हमें जीवन में सफल होना सिखातीं हैं। ख़राब परिणाम देखकर कभी-कभी बच्चे अतिवादी कदम(आत्महत्या तक) उठा लेते हैं और वे घोर तनाव से और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जीवन उन्हें नीरस-नीरस सा लगने लगता है, ऐसे में अभिभावक और शिक्षकों को यह चाहिए कि वे अपने बच्चों को किसी भी हाल और परिस्थितियों में निराश नहीं होने दें, और उनमें सकारात्मक सोच विकसित कर उन्हें लगातार प्रेरित व प्रोत्साहित करें। वास्तव में, असफलता ही सफलता की असली सीढ़ी है, जो हमें सिखाती है और हमारे विकास में मदद करती है ।असफलता से हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और इससे हम मजबूत बनते हैं। हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि असफलता मिलने पर निराश नहीं होना है, बल्कि इससे हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ।सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है ।असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम और मजबूत बन सकते हैं। हमें बच्चों को ठोस योजना बनाने में मदद करनी चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि वे अपने लक्ष्य निर्धारित करें, योजना

बनाएं, और योजनाओं को सफल करने में जुट जाएं। कोई भी असफलता हमें अपनी कमजोरियों को समझने और सुधार करने का मौका देती है। हम अपने बच्चों को यह बताएं कि जीवन में आत्म-विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में, असफलता से सीखते हुए हम और मजबूत बनते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं ।असफलता से हमें अनुभव मिलता है जो हमें भविष्य में बेहतर तरीके से तैयार करता है ।असफलता से हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जो हमारी प्रगति पथ को नई दिशा देता है। बहरहाल, मई जून का समय हमारे यहां स्कूली नतीजों के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने का भी समय होता है और ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में बच्चों को सकारात्मक वातावरण प्रदान करने, उन्हें संघर्ष करने का काम केवल माता-पिता, अभिभावक और शिक्षक ही कर सकते हैं। वास्तव में, माता-पिता, अभिभावकों को बच्चे की कोशिशों की सराहना करनी चाहिए, उन्हें नकारात्मकता से दूर रखना चाहिए, और उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करना चाहिए । याद रखिए कि बच्चे की मेहनत को पहचानना और उसे सफल बनाने में मदद करना, यह महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को यह चाहिए कि वे अपने बच्चों को उनकी इच्छा और रूचि के हिसाब से सही गाइडेंस लेकर ही विषयों का चुनाव करवाए। अभिभावकों को बच्चों पर विषय विशेष के चुनाव को लेकर कोई भी दवाब नहीं डालना चाहिए। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि अपेक्षित अंक न आने पर बच्चे टूट जाते हैं और माता-पिता की नाराज़गी से उनका आत्मविश्वास और भी गिर जाता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि हाल ही में अलीगढ़ के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने बेटे की सीबीएसई कक्षा 12वीं की मार्कशीट को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उनके बेटे को मात्र 60% अंक मिले, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना केवल बेटे को बधाई दी, बल्कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए मोटिवेशनल संदेश-'जीवन को कहीं से भी, कभी भी शुरू किया जा सकता है। मेरे बेटे ने 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। बेटे को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।' लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि-'रिजल्ट नहीं, नजरिया मायने रखता है।' बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि कोई भी माता पिता बच्चों से बहुत सी अपेक्षाएं रखता है, लेकिन दुखद बात यह है कि हम सफलताओं या असफलताओं की स्वीकार्यता के प्रति नयी पीढ़ी को मानसिक रूप से तैयार नहीं करते ।हम हमेशा अपने बच्चों की तुलना दूसरों बच्चों से करते हैं, लेकिन तुलना दूसरों से नहीं की जानी चाहिए, क्यों कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत अंतर पाये जाते हैं। परीक्षा परिणाम के समय बच्चों को संबल प्रदान किया जाना बहुत आवश्यक और जरूरी है। हमें यह चाहिए कि हम अपने बच्चों को यह समझाएं कि किसी परीक्षा विशेष में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है। होना तो यह चाहिए कि हम अपने बच्चों को असफलताओं का सामना करना सिखाएं। वास्तव में जब हम दिशाहीन होते हैं, हमारे लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं, तभी हम असफल होते हैं। ज्ञानीजन कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन को एक बड़ी संभावना को हासिल करने की दिशा में एक क़दम बना लें, तो फिर असफलता नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। सच तो यह है कि सफलता किसी और का विचार है। हमारे धर्म, समाज और संस्कारों ने हमें ऐसा मानने के लिये प्रशिक्षित किया है ।वह जो इस जीवन को एक बड़ी संभावना को पाने की दिशा में एक शुरुआती क़दम के रूप में देखता है, उसके लिये असफलता जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों का उपयोग अपने आपको ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिये कर सकते हैं, या फिर बैठ कर रो सकते हैं। हमारे पास यही विकल्प हैं और सफलता और असफलता हमारे स्वयं पर निर्भर है। हम अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। वास्तव में, असफलता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये बस एक विचार है, क्योंकि सफलता भी एक मूर्खता से भरा विचार ही है। हमें यह चाहिए कि हम दुनिया को बदलने की बजाय अपनी इस सोच को बदलें। अगर हम बस वही बदल देते हैं तो सब कुछ बढ़िया हो जायेगा।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

हिसार की बेटी और भिवानी की बहू प्रियंका सौरभ को मिला 'सामाजिक सरोकार पत्रकारिता नारद सम्मान 2025'

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मानव रचना यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में किया सम्मानित

हिसार/ भिवानी/फरीदाबाद, हरियाणा। देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में हरियाणा की चर्चित लेखिका, कवयित्री एवं स्वतंत्र पत्रकार प्रियंका सौरभ को 'सामाजिक सरोकार पत्रकारिता नारद सम्मान – 2025' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा मानव रचना यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद के सभागार में प्रदान किया गया।

प्रियंका सौरभ, जो हिसार के गाँव आर्य नगर की बेटी और भिवानी के गाँव बड़वा की बहू हैं, ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की पक्षधरता की है। उनका लेखन जनसरोकारों की आवाज़ बन चुका है।

इस आयोजन का सफल संचालन विश्व संवाद केंद्र, हरियाणा द्वारा किया गया, जो पिछले 10 वर्षों से देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित करता आ रहा है। इस वर्ष का आयोजन 25 मई 2025 को किया गया।

विश्व संवाद केंद्र, हरियाणा के सचिव श्री राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, "देवर्षि नारद भारतीय पत्रकारिता के आदर्श माने जाते हैं। आज के संदर्भ में ऐसे पत्रकारों को सम्मानित करना ज़रूरी है, जो निडर होकर समाज की सच्चाइयों को सामने लाते हैं। प्रियंका सौरभ का लेखन इसी

विचारधारा को आगे बढ़ाता है।"

सम्मान स्वीकार करते हुए प्रियंका सौरभ ने कहा, "यह सम्मान मेरी कलम का नहीं, उन आवाज़ों का है जिन्हें समाज अक्सर अनसुना कर देता है। मैं प्रयासरत हूँ कि मेरी लेखनी उनके हक और हकीकत को सामने लाती रहे।"

अलीगढ़ में गोमांस के शक में मुसलमानों पर बर्बर हमला

जमीयत के प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की*

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली : जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी ने अलीगढ़ में चार मुस्लिम व्यापारियों पर भीड़ द्वारा किए गए बर्बर हमले को अमानवीय और देश के लिए शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि गोमांस के शक में मुस्लिम युवकों को पीटना शांति और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सख्त कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद गौरक्षक समूह बेखौफ होकर लोगों की जान के पीछे पड़े हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है।

मौलाना मदनी ने कहा कि सरकारों को स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और देश में कानून के दायरे से बाहर कोई भी समूह इस तरह का तथाकथित इंसाफ करने का हकदार नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अमल में लाया जाना चाहिए।

उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी जांच की जाए। सभी हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ माब लिंचिंग रोधी कानून और अन्य कड़े धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। घायलों के समुचित इलाज, सुरक्षा और मुआवजे का इंतज़ाम किया जाए।

यह उल्लेखनीय है कि घटना की जानकारी मिलते ही जमीयत उलेमा शहर अलीगढ़ के अध्यक्ष मुफ्ती अकबर क़ासमी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल जेएनएमसी अस्पताल पहुंचा और घायलों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस सिलसिले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी को अलीगढ़ इकाई ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कहा गया है कि जमीयत के प्रतिनिधि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में हैं ताकि सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़ित मांस के व्यापारी हैं, उनके पास गैर-प्रतिबंधित जानवर का मांस था, जिसकी रसीद भी मौजूद थी, इसके बावजूद दंगाइयों ने कुछ नहीं सुना।

जानिए कोंन सी बातें है अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध

रजत कल्सन

अगर कोई गैर अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय का व्यक्ति

1. किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को कोई घृणित या अखाद्य या अपशिष्ट पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करें या जबरदस्ती उसके मुंह में डालें

2. किसी अनुसूचित जाति /जनजाति समुदाय के व्यक्ति के घर, जमीन, प्लाट या द्वार पर किसी इंसान मलमूत्र, किसी जानवर का मलमूत्र, किसी जानवर का शव या कोई अन्य घृणित पदार्थ डालना

3. किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को जानबूझकर चोट मारने ,नुकसान पहुंचाने , परेशान करने या अस्वस्थ करने की नियत से उसके घर के सामने या पड़ोस में मलमूत्र डालना, किसी जानवर का शव डालना, कूड़ा करकट डालना, या कोई अन्य घृणित पदार्थ डालना।

4. किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति के गले में चप्पल -जूतों का हार डालकर या उसे नग्न या अर्धनग्न हालत में सार्वजनिक स्थानों पर परेड कराना

5. किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति का उसके मानवाधिकारों के विरुद्ध जबरदस्ती उसे गंजा करना, उसकी दाढ़ी-मूंछें साफ करना , उसके कपड़े उतरवाना या उसके शरीर को रंगना या मुंह पर जबरदस्ती कालिख पोतना

6. किसी अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति की मलकियत वाली या अलाट की गई, ट्रांसफर की गई या उसके कब्जे वाली या सरकार द्वारा इसके हक में इस तरह की अधिसूचित जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करना या जबरदस्ती उस पर खेती करना

7. किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति की मलकियत या कब्जे वाली जमीन से जबरदस्ती कब्जा छिनना या उस कब्जे के साथ जंगल से जुड़े हुए अधिकार तथा सिंचाई व पानी से जुड़े हुए अधिकारो से उसे वंचित करना व उसकी जमीन पर उगी फसल को नष्ट करना या लूटना

8. किसी अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के व्यक्ति से जबरदस्ती बेगार या बंधुआ मजदूरी कराना।

9. किसी अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के व्यक्ति से जबरदस्ती किसी मानव या जानवर का शव उठवाना या उस उद्देश्य के लिए कोई क़ब्र खोदने के लिए मजबूर करना

10. अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को मानव मल ढोने के लिए मजबूर करना या उसे इस तरह के किसी व्यवसाय या नौकरी करने के लिए मजबूर या प्रेरित करना

11. किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय की महिला या पुरुष को धार्मिक संस्थान, मंदिर या स्थान में किसी देवता ,राक्षस , प्रतिमा या पूजा का पात्र बनने के लिए मजबूर करना व इस काम के लिए बढ़ावा देना या देवदासी जैसी प्रथा के लिए मजबूर करना या इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना।

12. चुनाव के समय कानून के विरुद्ध किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए मजबूर करना तथा अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ने से रोकना या उसको अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर करना या किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक बनने से रोकना

13. अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय का व्यक्ति जो संविधान के तहत किसी पंचायत या पंचायत समिति या अन्य किसी पंचायत निकाय में किसी पद पर है उसे उसकी कानूनी व संवैधानिक ड्यूटी करने से रोकना या संविधान विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करना या धमकी देना

14. चुनाव के बाद किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को चोट मारना, उस पर हमला करना या उसे गंभीर चोटें मारना या उसका या उसके समुदाय का जानबूझकर सामाजिक बहिष्कार करना करके उसे सामाजिक सुविधाओं का फायदा लेने से रोकना।

15. चुनाव के दौरान किसी अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने या ना डालने के लिए इस कानून के तहत अपराध करना

16. किसी अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के व्यक्ति खिलाफ झूठी दुर्भावनापूर्ण तथा कष्टकर कानूनी व आपराधिक कार्रवाई करना

17. अनुसूचित जाति व जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध किसी लोकसेवक को झूठी व दुर्भावनापूर्ण शिकायत करना ताकि लोकसेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के व्यक्ति को परेशान करने या उसे कष्ट पहुंचाने में करे ।

18. अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति का अपमान करने या उसे नीचा दिखाने के नियत से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनता की मौजूदगी में उसका अपमान करना

19. किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति का अपमान करने की नियत से या उसे नीचा दिखाने के लिए उसे जातिसूचक गालियां बकना

20. किसी ऐसी वस्तु या प्रतिमा जो दलित समाज के लिए में उच्च सम्मान व पवित्रता रखती हो उसे तोड़ना, नष्ट करना या अशुभ करना।

21. अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के प्रति मौखिक, लिखे हुए शब्दों द्वारा या इशारो या किसी विरोध पत्र द्वारा दुश्मनी की भावना, नफरत ,वैरभाव को बढ़ावा देना या बढ़ाने का प्रयास करना

22.अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के महान पुरुषों, संतो प्रति मौखिक, लिखे हुए शब्दों द्वारा या इशारो या किसी विरोध पत्र द्वारा उनका अपमान या अनादर करना या करने का प्रयास करना

23. यह जानते हुए कि यह महिला अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय से है उसे किसी योन हिंसा / छेड़खानी करने की नियत उक्त महिला की मर्जी के बगैर से छूना

24. यह जानते हुए कि महिला या युवती अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय से है उसके तरफ जानबूझकर यौन हिंसा या छेड़खानी की नियत से भद्दे इशारे करना ,फब्तियां कसना या अश्लील हरकतें करना ।

25. आमतौर पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जलाशय या पानी के स्त्रोत को जानबूझकर उक्त व्यक्ति या समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए दूषित करना, रोकना या अशुद्ध करना

26. अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को किसी परंपरागत रास्ते का इस्तेमाल कर किसी अड्डे, रिसोर्ट जाने से रोकना या किसी सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा करना जिनका इस्तेमाल करने का अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का हक हो

27. अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय को या उसके किसी सदस्य को कोई गांव ,घर या कोई अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना या इस तरह के हालात पैदा करना

28. किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय को किसी इलाके की सामुदायिक या सांझी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से रोकना या किसी दफनाने की जगह या अंतिम संस्कार की जगह का प्रयोग करने से या दलित समाज को किसी सामुदायिक या सांझा जल स्त्रोत, जलाशय, पानी की डिग्गी, नाला, नदी, नलकूप या किसी पब्लिक सुविधा केंद्र, रास्ता, सड़क को इस्तेमाल करने से रोकना

29. अनुसूचित जाति या जनजाति समाज के लोगों को साइकिल यात्रा करने से ,मोटरसाइकिल पर जुलूस निकालने से या किसी शादी या शुभ अवसर पर या दुख के अवसर पर कोई जुलूस निकालने, शादी या किसी शुभ अवसर पर घोड़ी चढ़ने या किसी वाहन में बैठने से रोकना।

30. अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय की किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थान में घुसने से रोकने या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह या जुलूस में हिस्सा लेने या शामिल होने से रोकना

31. अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की लोगों को किसी शिक्षण संस्थान ,अस्पताल ,डिस्पेंसरी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, दुकान या पब्लिक एंटरप्राइजेज या किसी और सार्वजनिक स्थान पर घुसने या उसका प्रयोग करने से रोकना या किसी बर्तन या किसी वस्तु जो सामुदायिक इस्तेमाल के लिए किसी सार्वजनिक जगह पर रखी हुई है उसका इस्तेमाल करने से रोकना

32. अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को किसी व्यवसाय , धंधा करने जीविका चलाने ,कोई बिजनेस करने या किसी जगह नौकरी करने से रोकना जहां पर अन्य समुदायों के लोग नौकरी करने का अधिकार रखते हैं

33. जादू टोना या डायन प्रथा के नाम पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को चोट मारना, परेशान करना या उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाना

34 . अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय का सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करना या बहिष्कार करने की धमकी देना

35. अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की नियत से उसके खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा सबूत यह जानते हुए कि झूठे सबूत या शिकायत की वजह से अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को मौत तक की सजा हो सकती है को लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत करना और यदि इस तरह के झूठे व मनगढ़ंत सबूत के आधार पर किसी निर्दोष अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को सजा हो जाती है तो ऐसा अपराधियों को मौत की सजा से दंडित किया जाएगा

36. अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की नियत से उसके खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा सबूत यह जानते हुए कि झूठे सबूत या शिकायत की वजह से अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को सात साल या अधिक तक की सजा हो सकती है को लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत करना और यदि इस तरह के झूठे व मनगढ़ंत सबूत के आधार पर किसी निर्दोष अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को सजा हो जाती है तो ऐसा अपराधियों को सात साल की सजा से दंडित किया जाएगा

37. किसी दलित समुदाय के व्यक्ति के घर में कोई ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ यह जानते हुए रखना कि इससे उस अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है तो ऐसे अपराधी को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

38. अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के व्यक्ति के घर में जानबूझकर आग लगाने या विस्फोट करने, यह जानते हुए कि जिस स्थान या प्रोपर्टी आग लगाई जा रही है वह इंसानों के रहने के लिए है या पूजा का स्थान है तथा दलित समुदाय के व्यक्ति के कब्जे में है अगर कोई गैर अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्ति यह अपराध करता है तो उसे कम से कम उम्र कैद व जुर्माने के साथ सजा सुनाई जाएगी।

39. यदि कोई गैर अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के व्यक्ति को यह जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय से है , यह जानते हुए उसके साथ कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं में कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है उस दशा में एक्ट की धारा 3(2)(5) स्वयं आकर्षित हो जाएगी तथा इस धारा के तहत आरोपी को कम से कम उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी।

40. यदि कोई गैर अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति या प्रॉपर्टी को जानते हुए यह है दलित समुदाय से संबंधित है कोई ऐसा अपराध करता है जो भारतीय दंड संहिता के तहत भी अपराध है तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा

41. यदि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के व्यक्ति खिलाफ कोई अपराध होने की जानकारी है या उस पर विश्वास करने का कारण है तथा कोई गैर अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्ति इससे संबंधित कोई सबूत को इस नियत से नष्ट करता है ताकि अपराधी को कानूनी सजा से बचाया जा सके या इस संबंध में कोई झूठी जानकारी लोक सेवक को देता है तो वह इस बारे में दंडित किया जाएगा।

42. यदि कोई आरोपी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तथा वह कोई लोकसेवक या कर्मचारी भी है तो उसे कम से कम 1 साल के कारावास या किये गए अपराध में दी गयी सजा को भुगतना होगा ।

43. यदि कोई सरकारी अधिकारी जो गैर अनुसूचित जाति समुदाय से है जानबूझकर अपनी सरकारी ड्यूटी को अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए लापरवाही से प्रयोग करता है तो उसे कम से कम 6 माह और जो 1 साल तक हो सकेगी व जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

नोट-:- अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत वर्णित अपराध नान कंपाउंडटेबल है। इन अपराधों में समझौता नहीं किया जा सकता तथा इन अपराधों में शिकायतकर्ता, पुलिस या ट्रायल कोर्ट को भी समझौता कराने का अधिकार नहीं है यदि कोई शिकायतकर्ता अदालत के सामने गवाही के दौरान समझौते करने की नियत से अपने बयानों से मुकरता है तो सरकार को तथा अदालत को उस शिकायतकर्ता के खिलाफ कानून प्रक्रिया संहिता की धारा 340 व 195,193, 182 के तहत मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार होगा जिसमें उसे शिकायतकर्ता को सजा हो सकती है।

अधिवक्ता व दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता

26 मई की क्रांति: नया भारत, नया विश्वास - मोदी युग का शंखनाद

एक सामान्य व्यक्ति जब असाधारण संकल्प लेकर उठता है, तो इतिहास स्वयं रास्ता बनाता है - यह कथन 26 मई 2014 को उस ऐतिहासिक पल में साकार हुआ, जब नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह दिन केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि एक नए भारत की नींव, एक नई आशा और एक नई दिशा का प्रतीक था। यह वह क्षण था जब भारत ने न केवल एक नेता चुना, बल्कि एक दृष्टिकोण, एक ऊर्जा और एक क्रांति को गले लगाया। उस दिन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गूंजी शपथ की आवाज़ देश के 125 करोड़ दिलों में उम्मीद की लहर बनकर दौड़ी। अब, 2025 में, जब हम उनके 11 वर्षों के नेतृत्व को देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि यह दिन केवल एक शुरुआत थी—एक ऐसे युग की, जिसने भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाया।

नरेंद्र मोदी की कहानी किसी परीकथा से कम नहीं। गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में जन्मे, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले उस बालक ने कभी सपने देखे थे, जो असंभव लगते थे। लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। चाय की केतली से लेकर देश की कमान तक का उनका सफर हर भारतीय को प्रेरित करता है। यह केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो कहता है—सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। मोदी का व्यक्तित्व केवल प्रभावशाली नहीं, बल्कि प्रेरणादायी है। उनकी सादगी, स्पष्टवादिता और जनता से सीधा संवाद उन्हें आम नेताओं से अलग करता है। 2014 के चुनावों में उनकी आवाज़—"मैं 125 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रतिनिधि हूं"—हर घर, हर गाँव तक पहुंची। यह नारा नहीं, बल्कि एक विश्वास था, जिसने देश को एकजुट किया। जनता ने उनमें एक ऐसे नेता को देखा, जो सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि उन्हें पूरा करने का जज़्बा रखता है।

26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तो यह केवल एक सरकार का गठन नहीं था, बल्कि एक नए युग का प्रारंभ था। इस दिन की सबसे खास बात थी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना। यह कदम न केवल कूटनीतिक था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और वैश्विक मंच पर उसकी नई भूमिका का प्रतीक था। यह संदेश था कि भारत अब केवल अपने विकास पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग और समृद्धि की नई कहानी लिखेगा। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल परिवर्तनकारी नीतियों और निर्णायक नेतृत्व का गवाह बना। जन धन योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, जिससे वित्तीय समावेशन का सपना साकार हुआ। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया, जिसने न केवल शहरों बल्कि गाँवों की तस्वीर बदली। उज्ज्वला योजना ने लाखों महिलाओं को धुएं से भरी रसोई से मुक्ति दिलाई। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहल ने भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की राह पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया।

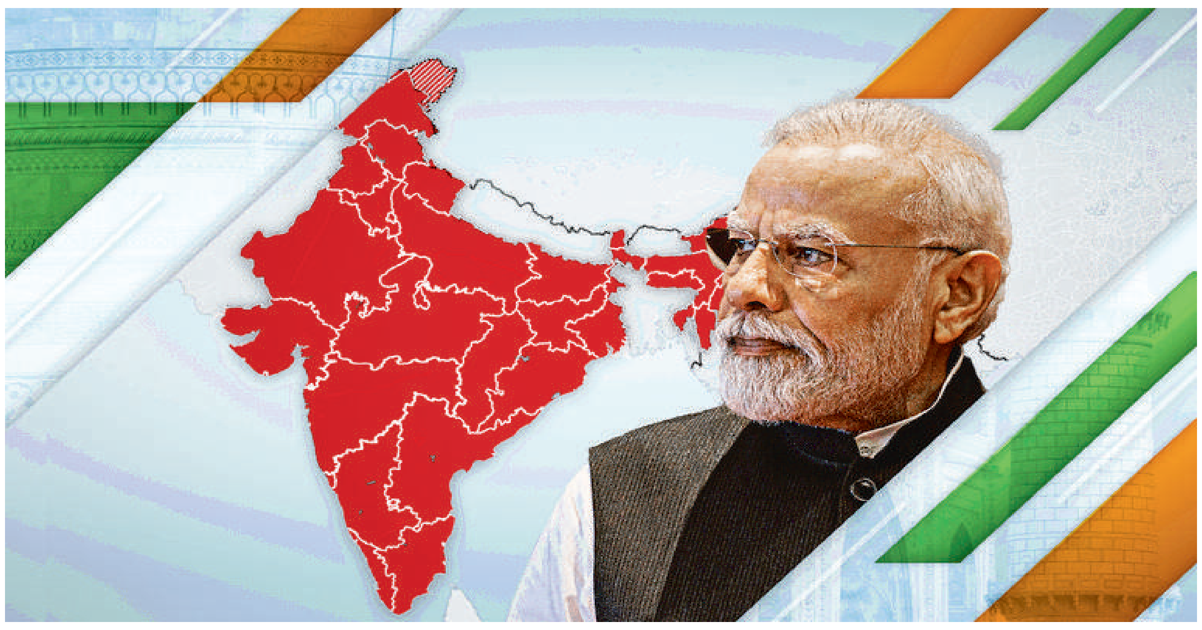

मोदी का प्रशासनिक कौशल उनकी नीतियों की गति और स्पष्टता में झलकता है। उन्होंने लालफीताशाही को चुनौती दी, सरकारी तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया। चाहे वह जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में सुधार हो या आयुष्मान भारत के जरिए गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना, हर कदम में उनकी सोच स्पष्ट थी—भारत को सशक्त और समृद्ध बनाना। विदेश नीति में नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो न केवल अपनी बात रखती है, बल्कि दुनिया को दिशा भी देती है। संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता हो या जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व, मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ को बुलंद किया। उनकी कूटनीति में संतुलन और आत्मविश्वास का अनूठा संगम दिखता है। चाहे वह अमेरिका, रूस, जापान या अरब देशों के साथ संबंध हों, हर कदम पर भारत की गरिमा और हित सर्वोपरि रहे। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को एक सशक्त और जवाबदेह राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। ऑपरेशन सिंदूर इस दृढ़ संकल्प का ज्वलंत उदाहरण है, जिसने न केवल आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, बल्कि विश्व पटल पर भारत की निर्णायक और निडर छवि को और मजबूत किया।

नरेंद्र मोदी का नेतृत्व केवल योजनाओं और नीतियों तक सीमित नहीं है। उनका दृष्टिकोण हर भारतीय को सशक्त बनाने का है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास" उनका वह मंत्र है, जो भारत के समावेशी विकास को परिभाषित करता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जो हर भारतीय को यह विश्वास दिलाता है कि वह देश के विकास का हिस्सा है। 26 मई 2014 का दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के नवजागरण का प्रतीक है। यह वह दिन था जब देश ने अतीत की जड़ता को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने न केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों के सपनों को अपने कंधों पर उठाया। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं।

आज जब हम उस दिन को याद करते हैं, तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। 26 मई 2014 ने भारत को एक नया आत्मविश्वास दिया, एक नया जोश भरा और एक नई उम्मीद जगाई। नरेंद्र मोदी केवल एक नेता नहीं, बल्कि उस विश्वास का नाम हैं, जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है—"मैं भारत हूं, और मैं बदल रहा हूं।" यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब संकल्प और नेतृत्व एक साथ मिलते हैं, तो इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य रचा जाता है। आज जब हम उस ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं, तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। नरेंद्र मोदी केवल एक नेता नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों और नेतृत्व में दृढ़ता हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। 2025 में, भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल बदल रहा है, बल्कि विश्व मंच पर अपनी एक नई पहचान रच रहा है। यह वह भारत है, जो कहता है—"हम भारत हैं, और हमारा भविष्य उज्ज्वल है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

सांसे अटकी जैसे कोई कहर उठा... !

इन बादलों की गर्जना से आसमान दहल उठा,
यात्रियों की सांसे अटकी जैसे कोई कहर उठा।
दिल्ली-श्रीनगर जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट,
छत्तीस हज़ार फीट ऊंचाई पे हिचकोले हाईट।
आसमान में हवा से ज़्यादा ज़रूरत ज़मीन की,
मगर पडोसी की इंसानियत बहुत ही ज़हीन थी।
इन बादलों की गर्जना से आसमान दहल उठा,
यात्रियों की सांसे अटकी जैसे कोई कहर उठा।
एक नियमित उड़ान पठानकोट का आसमान,
तभी पायलट के रडार पे आया भीषण तूफान।
ऐसे हालात में वापस लौटो या वैकल्पिक रूट,
दायीं ओर तूफान और बाईं ओर हैं पाकिस्तान।
इन बादलों की गर्जना से आसमान दहल उठा,
यात्रियों की सांसे अटकी जैसे कोई कहर उठा।
ज़िंदगी और मौत के बीच एक पतली सी रेखा,
इसे पार पाने की चाबी को पाकिस्तान ने देखा।
मानवीय आधार पे लाहौर से ही की थी विनती,
पाक इंसानी परीक्षा में हुआ फेल भूला गिनती।
इन बादलों की गर्जना से आसमान दहल उठा,
यात्रियों की सांसे अटकी जैसे कोई कहर उठा।
यह ना केवल एक राजनीतिक इनकार भर था,
ये मानवता के विरुद्ध मौन हो रहा अपराध था।
अगर पायलट यहाँ थोड़ी भी चूक कर जाता,
यात्रियों का परिवार एवं देश शोक में डूब जाता।

संजय एम तराणेकर

वर्क फ्रॉम होम कल्चर: सुविधा की दुनिया या अकेलेपन की कैद?

वैश्विक महामारी ने जब पूरी दुनिया को एक अनजान ठहराव में धकेल दिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि घर की चारदीवारी, जो हमेशा से विश्राम और निजता का प्रतीक रही, एक दिन कार्यस्थल में तब्दील हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जो पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसने कार्य की परिभाषा को फिर से गढ़ा, समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ा, और हमें एक ऐसी दुनिया में ले आया, जहां सुबह की कॉफी और ऑफिस डेस्क एक ही मेज पर सिमट गए। लेकिन यह बदलाव, जो बाहर से लचीलापन और सुविधा का प्रतीक दिखता है, क्या वाकई इतना सरल है? या यह हमें एक ऐसी राह पर ले जा रहा है, जहां सामाजिक रिश्तों की गर्माहट धीरे-धीरे डिजिटल स्क्रीनों की ठंडक में खो रही है?

वर्क फ्रॉम होम ने निस्संदेह कई द्वार खोले हैं। सुबह की भागदौड़, ट्रैफिक की जाम में खोया हुआ समय, और ऑफिस के औपचारिक माहौल से मुक्ति ने कर्मचारियों को एक नई आजादी दी। अब आप अपने पसंदीदा पजामे में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ दोपहर का खाना खा सकते हैं, और अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। छोटे बच्चों के माता-पिता के लिए यह व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं। बड़े शहरों में, जहां किराए और यातायात का खर्च जेब पर भारी पड़ता था, वहां इसने आर्थिक राहत भी दी। कंपनियों के लिए भी यह फायदेमंद रहा। ऑफिस स्पेस, बिजली, और अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च कम हुआ, जिससे कई संगठनों ने इस मॉडल को स्थायी रूप से अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। तकनीक ने इसे और आसान बनाया — हाई-स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और क्लाउड-बेस्ड टूल्स ने कार्य को निर्बाध बना दिया। लेकिन क्या यह सुविधा वाकई उतनी मुक्तिदायक है, जितनी दिखती है?

हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और वर्क फ्रॉम होम का सिक्का भी इसका अपवाद नहीं। इस व्यवस्था ने जहां समय और संसाधनों की बचत की, वहीं यह कर्मचारियों को एक अनजाने एकाकीपन की ओर भी धकेल रहा है। ऑफिस की वह अनौपचारिक बातचीत, कॉफी मशीन के पास होने वाली हंसी-मजाक, और सहकर्मियों के साथ विचार-विमर्श की गर्मजोशी अब स्क्रीन की औपचारिकता में सिमट गई है। 'जूम थकान' अब एक वास्तविकता है। घंटों स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना, लगातार वर्चुअल मीटिंग्स में शामिल होना, और संवाद का केवल कार्य-केंद्रित रह जाना — यह सब मानसिक थकान को जन्म दे रहा है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि लंबे समय तक सामाजिक संवाद की कमी न केवल चिड़चिड़ापन और तनाव को बढ़ाती है, बल्कि अवसाद और अकेलेपन की भावना को भी गहरा करती है। एक सर्वे के अनुसार, 2024 में 65% से अधिक कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम के दौरान अकेलापन महसूस करने की बात स्वीकारी। यह आंकड़ा अपने आप में इस नई कार्य-संस्कृति के छिपे खतरों को उजागर करता है।

इसके अलावा, वर्क फ्रॉम होम ने कार्य और निजी जीवन की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। पहले जहां ऑफिस से घर लौटना एक मानसिक बदलाव का प्रतीक था, अब काम और घर एक ही स्थान पर सिमट गए हैं। बॉस का देर रात मैसेज करना, वीकेंड पर तत्काल काम की मांग, और 'ऑलवेज ऑन' की संस्कृति ने कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डाला है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, जिनके पास घर में एकांत कार्यस्थल या विश्वसनीय इंटरनेट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है, या उन परिवारों में, जहां एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं, वहां वर्क फ्रॉम होम एक बोझ बन जाता है। महिलाओं के लिए यह दोहरी मार है। घरेलू जिम्मेदारियों और नौकरी के दबाव के बीच संतुलन बनाना उनके लिए एक कठिन चुनौती बन गया है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 70% से अधिक कामकाजी महिलाओं ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम ने उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है, जिससे उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा।

वर्क फ्रॉम होम ने कार्यस्थल की समानता को भी प्रभावित किया है। हर कर्मचारी के पास समान संसाधन या परिस्थितियां नहीं होतीं। एक व्यक्ति के लिए घर से काम करना शांत और उत्पादक हो सकता है, वहीं दूसरे के लिए यह बच्चों की आवाज, घरेलू काम, या खराब इंटरनेट के बीच जूझना हो सकता है। यह असमानता न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि करियर की प्रगति में भी बाधा बनती है। उदाहरण के लिए, जो कर्मचारी ऑफिस में उपस्थित रहकर नेटवर्किंग और नेतृत्व के अवसर प्राप्त करते थे, वे अब हाइब्रिड मॉडल में बेहतर स्थिति में हैं, जबकि पूर्णकालिक घर से काम करने वाले कर्मचारी अक्सर 'आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड' की स्थिति का शिकार हो रहे हैं।

इस बदलाव ने प्रबंधन की भूमिका को भी फिर से परिभाषित किया है। अब एक अच्छा लीडर वही है, जो न केवल टारगेट और डेडलाइन सेट करे, बल्कि कर्मचारियों की मानसिक स्थिति को समझे, उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो, और एक ऐसी संस्कृति बनाए, जहां संवाद और सहयोग बरकरार रहे। कई कंपनियां अब हाइब्रिड मॉडल की ओर बढ़ रही हैं, जो घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। यह मॉडल न केवल कर्मचारियों को सामाजिक जुड़ाव का अवसर देता है, बल्कि लचीलापन भी बनाए रखता है। लेकिन इसके लिए संगठनों को कर्मचारियों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। उदाहरण के लिए, मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों, जैसे काउंसलिंग या वेलनेस प्रोग्राम्स, को बढ़ावा देना, और कार्य के घंटों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है।

वर्क फ्रॉम होम एक तलवार की धार की तरह है — एक ओर यह स्वतंत्रता और सुविधा देता है, दूसरी ओर यह हमें सामाजिक और मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम केवल उत्पादकता की दौड़ में हैं, या एक ऐसी कार्य-संस्कृति की तलाश में, जो हमें इंसान बनाए रखे। तकनीक ने हमें जोड़ा, लेकिन यह रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। हमें यह तय करना होगा कि हमारा भविष्य कैसा हो — एक ऐसी दुनिया, जहां स्क्रीन पर टिमटिमाते चेहरे ही हमारा एकमात्र संवाद हों, या एक ऐसी व्यवस्था, जहां तकनीक और इंसानियत एक साथ चलें। अगर हम अभी नहीं चेते, तो सुविधा के इस भूलभुलैया में हमारा सामाजिक ताना-बाना कहीं खो जाएगा। और तब हमारे पास न ऑफिस की हलचल होगी, न घर की रौनक — केवल एक डिजिटल स्क्रीन, जो हमें अगली मीटिंग की याद दिलाएगी, और फिर खामोश हो जाएगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

अब कोई रोक नहीं सकता — भारत चल पड़ा है [जापान पीछे, भारत आगे — कहानी बदली है]

भारत आज वैश्विक मंच पर एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अपनी आर्थिक प्रगति, नीतिगत मजबूती और नेतृत्व की दूरदर्शिता से दुनिया को चकित कर रहा है। जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़कर भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की उस अथक मेहनत और विजन का परिणाम है, जिसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत की यह प्रगति केवल आंकड़ों की जीत नहीं है, बल्कि यह उस नेतृत्व की कहानी है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बन चुकी है।

जापान को पीछे छोड़ना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत की नाममात्र जीडीपी 2025 में 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर रही। यह अंतर भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 2014 से 2025 के बीच औसतन 6-7% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है, जो मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को एक ऐसा माहौल दिया, जहां नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जो वैश्विक दिग्गजों को चुनौती दे रही है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत 2028 तक जापान को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा। आईएमएफ के प्रक्षेपण के अनुसार, भारत की जीडीपी 2028 तक 5.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि जापान की वृद्धि दर धीमी होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी नीतियों ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां बड़े-बड़े देश भारत के साथ सहयोग करने को आतुर हैं। भारत 2025 के अंत तक अपने जनसंख्यात्मक लाभांश का उपयोग करेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, और यह युवा शक्ति भारत की प्रगति का आधार बन रही है। स्किल इंडिया मिशन और नई शिक्षा नीति जैसे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि मोदी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोदी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उसने भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया है। विश्व बैंक की ₹ईज ऑफ डूइंग बिजनेस₹ रैंकिंग में भारत ने 2014 में 142वें स्थान से 2024 में 50वें स्थान तक की छलांग लगाई है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 2024 में 83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2014 के 36 बिलियन डॉलर से दोगुना से भी अधिक है। इसका कारण सरकार की स्थिर नीतियां और पारदर्शी शासन हैं। नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी भी बढ़ानी है। भारत में बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल तकनीक का विस्तार और कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए किए गए प्रयासों ने भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाया है, जो न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।

भारत की यह प्रगति केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014 में 1,560 डॉलर से बढ़कर 2025 में 2,900 डॉलर तक पहुंच गई है। यह सुधार इस बात का संकेत है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने हमेशा समावेशी विकास पर ध्यान दिया है। जन धन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली, और उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार का फोकस केवल बड़े आंकड़ों पर नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने पर भी है।

हालांकि, भारत को अभी कई चुनौतियों का सामना करना है। बेरोजगारी दर 2024 में 7.1% रही, और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभी और सुधार की जरूरत है। लेकिन यह भी सच है कि मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों में भी काम शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव किए गए हैं, और स्वास्थ्य बजट 2014 के मुकाबले 2025 में तीन गुना बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इस बात का प्रतीक है कि भारत न केवल अपनी कमजोरियों को पहचानता है, बल्कि उनसे निपटने के लिए ठोस कदम भी उठा रहा है। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को एक नई दिशा दी है।

भारत की यह प्रगति पूरे देश की मेहनत और लगन का नतीजा है। लेकिन इस मेहनत को सही दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। भारत आज एक ऐसा देश है, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करता है, और साथ ही आधुनिकता को अपनाने में भी पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसा मंच दिया है, जहां वह अपनी क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकता है।

जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत के लिए गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ताकत को दर्शाती है। उनकी नीतियों और विजन ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां वह न केवल अपनी प्रगति पर गर्व कर सकता है, बल्कि दुनिया को भी प्रेरित कर सकता है। भारत का भविष्य उज्ज्वल है, और इस उज्ज्वल भविष्य को साकार करने में नरेंद्र मोदी का योगदान अतुलनीय है। यह समय है कि हम सभी इस उपलब्धि पर गर्व करें और भारत को और आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर काम करें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, और यह यात्रा अभी शुरू हुई है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023